

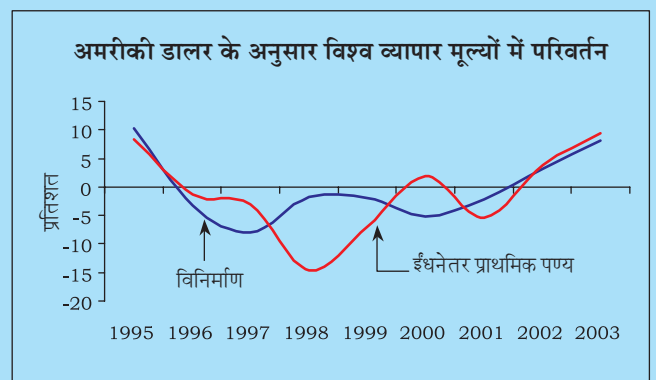
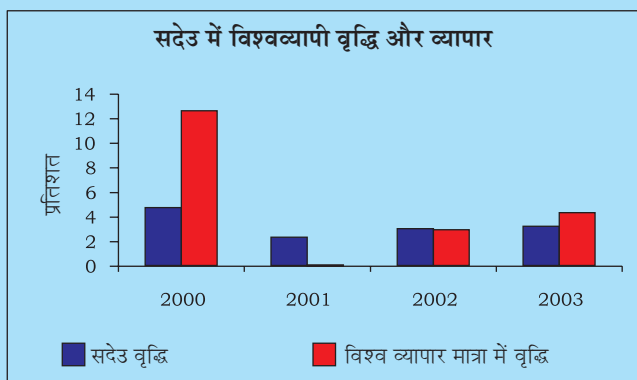
6.1 वर्ष 2002-03 में एक ऐसे वातावरण में जहां विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि में दुर्बलता, इक्विटी बाजार में गिरावट और भौगोलिक-राजनीतिक अनिश्चितताएं हावी रही हों, गतिशील और विशाखीकृत निर्यात कार्य की उपलब्धियों ने भारत के बाह्य क्षेत्र की बढ़ती हुई शक्ति और उसकी ऊर्जस्विता को रेखांकित किया है। विश्व के अन्य भागों की अपेक्षा घरेलू औद्योगिक गतिविधियों के पुनरुत्थान की गति द्वारा आयात की मांग को बढ़ाया गया, तथापि, अग्रणी निर्यातक देशों में चीन के बाद भारत, विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते हुए निर्यातक देश के रूप में उभरा है और लगातार दूसरे वर्ष भी चालू खाते के भुगतान संतुलन में अधिशेष बना रहा है। समष्टिगत आधारभूत गतिविधियों में बढ़ते हुए विश्वास ने घरेलू स्तर पर एक विशेष प्रकार का रुझान पैदा कर दिया है। देश में ऋण की राशि के कम आगम और विदेशी निवेश के कम आने के बावजूद बैंकों, कंपनियों और निर्यातकों ने निवल वित्तीय राशियों का घरेलू आस्तियों के पक्ष में जिस प्रकार से पुनर्समायोजन किया है, उससे देश में आनेवाली निवल पूंजी में मजबूती आती गई है। चालू और पूंजी खाते के लेनदेनों में हुई अनुकूल गतिविधियां अमरीकी डालर के प्रति रुपये की विनिमय दर में आयी संतुलित वृद्धि के रूप में परिलक्षित हुई हैं। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के भण्डार में अभूतपूर्व संचय हुआ है, जो इस वर्ष की उभरती बाजार की अर्थव्यवस्थाओं में तीसरी सबसे बड़ी वृद्धि है। मार्च 2003 के अंत में भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां लगभग 14 महीने के आयात के बराबर अथवा पांच वर्षों के कर्जों की चुकौती के समकक्ष थीं, जो 'गुडडोटी नियम' (सामान्यतः विदेशी मुद्रा भंडार, आगामी वर्ष के दौरान उपयोग में लाई जानेवाली विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि, विदेशी मुद्रा ऋण की अनुसूचित चुकौती राशि से अधिक होनी चाहिए, यह मानते हुए कि किसी ऋण का रोल ओवर नहीं होगा) को

भलीभांति पूरा करता है। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों के इस बढ़ते हुए संचय से वर्ष के दौरान बहुपक्षीय और वाणिज्यिक ऋणों के समय-पूर्वभुगतान तथा अनिवासी जमाराशि की देयताओं की रकमों एवं उनकी परिपक्वता अवधि में बदलाव लाकर बाह्य ऋण को चुकाने की हमारी स्थिति और भी सुदृढ़ हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां

6.2 वर्ष 2002 में विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धि की स्थिति रुक-रुककर बढ़ी है, इराक युद्ध की अनिश्चितताओं, और इक्विटी बाजार में आये गुबार के फट पड़ने से वर्ष की चौथी तिमाही से आर्थिक वृद्धि की गति धीमी पड़ गयी। विश्व स्टॉक बाजारों में लगातार तीसरे वर्ष भी गिरावट की स्थिति बनी रही, क्योंकि निवेशकों का विश्वास निरंतर क्षीण बना रहा। विश्व व्यापार की मात्रा (वस्तुएं और सेवाएं) में विस्तार संतुलित बना रहा। ऐसा मुख्यतः इसलिए हो सका कि, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार एशियाई और संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं में जिस तेजी से उत्पादन में वृद्धि हुई है उसके कम से कम दुगुनी तेजी से व्यापार में वृद्धि हुई है और इसे आंतर-क्षेत्रीय मांग में हुई अत्यधिक वृद्धि से बल मिला है। गत कुछ वर्षों में अमरीकी डालर में हुई मूल्यवृद्धि ने अमरीकी डालर में मापी जानेवाली विश्व व्यापार कीमतों पर 'अपस्फीतिकारक' प्रभाव डाला है। वर्ष 2002 के दौरान अमरीकी डालर के मूल्यहास के कारण स्थिति उलट गई। विनिर्माताओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की जानेवाली कीमतें अमरीकी डालर में 1995 के बाद पहली बार बढ़ी हैं। अनाजों की व्यापार कीमतें, विशेष रूप से गेहूं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई, जो पांच पारंपरिक निर्यात क्षेत्रों में से चार क्षेत्रों में सूखे के कारण लगातार दूसरे वर्ष भी गेहूं के उत्पादन में हुई गिरावट को दर्शाती है। (चार्ट VI.1)।

चार्ट VI.1 : विश्वव्यापी उत्पादन और व्यापार



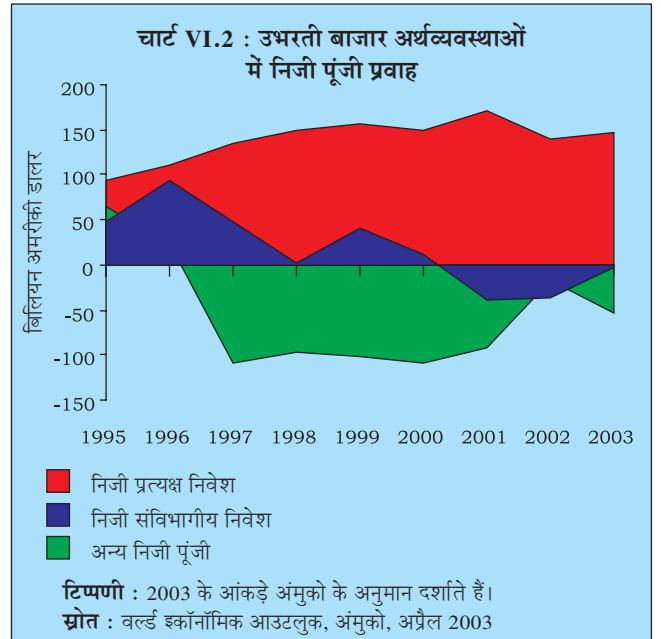
टिप्पणी : 2003 के आंकड़े अंमुको के अनुमान हैं।

स्रोत : वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक, अंमुको, अप्रैल 2003

6.3 उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विशेष रूप से एशियाई प्रशांत क्षेत्र में, समग्र सकल देशी उत्पाद में वृद्धि प्रतिकूल बाह्य गतिविधियों के बावजूद मजबूत बनी रही। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (इएससीएपी) के अनुसार यह क्षेत्र वर्ष 2002 में विश्व के सबसे तेज विकसित होनेवाले क्षेत्र के रूप में उभरा है। अक्टूबर 2002 से उभरते हुए बाजारों की वित्तीय स्थितियों में उभरते बाजार स्प्रेड में गिरावट के कारण भी सुधार आया है। यद्यपि, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में निवल निजी प्रत्यक्ष निवेश का प्रवाह कम रहा, किंतु अन्य निजी पूंजीगत प्रवाह के संतुलित बाह्य प्रवाह से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में होनेवाले निजी पूंजी प्रवाहों की मात्रा को बनाए रखा जा सका (चार्ट VI.2)। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के इन अंतर्वाहों से हुए कुछ सुधार से यह उम्मीद की जाती है कि ये प्रवाह वर्ष 2003 के दौरान थोड़े अधिक बने रहेंगे।

6.4 विश्वव्यापी मुद्रास्फीति की दर आमतौर पर नरम बनी रही, औद्योगिक देशों में यह दर अमरीका और यूरो क्षेत्र में उत्पादन में बढ़ते भारी अंतर के मद्देनजर दो प्रतिशत से नीचे बनी रही। कई एशियाई देशों में मुद्रास्फीति में हो रही गिरावट और जापान में चल रही मंदी को देखते हुए चौमुखी विश्वव्यापी अपस्फीति की संभावना पर चिंता व्यक्त की जा रही है। चूंकि अपस्फीति से काफी नुकसान पहुंचता है, इसलिए यह केंद्रीय बैंक के महत्त्व को रेखांकित करता है कि वह आवश्यकता पड़ने पर अपस्फीतिकारी प्रभावों को प्रारंभ में ही रोकने के लिए जोरदार और सुरक्षात्मक कार्रवाई करे (बॉक्स VI.1)।

6.5 अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (अंमुको) के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2003 में विश्वव्यापी सकल देशी उत्पाद और व्यापार की मात्रा में क्रमशः 3.2



प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत की मामूली-सी बढ़ोतरी हो सकती है। भौगोलिक-राजनीतिक अनिश्चितताओं में कमी, इक्विटी बाजार में स्थिरता आने तथा इन्वेंट्री चक्र में हुए परिवर्तन से यह उम्मीद की जाती है कि इससे विकास की संभावनाओं में सुधार आएगा। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के निभावकारी दृष्टिकोण के बावजूद प्रमुख करेंसी क्षेत्रों में होनेवाले समष्टिगत आर्थिक उत्प्रेरकों में विद्यमान अंतर साफ नजर आ रहा है। बृहत और बढ़ते हुए विश्वव्यापी समाष्टिगत आर्थिक असंतुलन से दीर्घकालीन विश्वव्यापी सुधार प्रक्रिया को बहुत बड़ा खतरा है (बॉक्स VI.2)।

बॉक्स VI.1

अपस्फीति - क्या यह विश्वव्यापी चिंता का विषय है ?

विश्व अर्थव्यवस्था वर्ष 2000 के उत्तरार्ध से लंबी मंदी के दौर से गुजर रही है जिसके साथ कतिपय औद्योगिक एवं उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में भी कीमतों में गिरावट का दौर चलता रहा है। वस्तुओं की कीमतों, खास तौर से नब्बे के दशक में हुई भारी गिरावट ने विनिर्माताओं और ईंधनेतर पण्यों दोनों की विश्व व्यापार कीमतों को प्रभावित किया है। इससे एशियाई संकट के बाद दूसरी बार व्यापक और स्थायी अपस्फीति का भय पैदा हो गया है।

विश्वव्यापी अपस्फीति का भय भारी उत्पादन अंतर (अर्थात् कई अर्थव्यवस्थाओं में क्षमता का आधिक्य), इक्विटी बाजार में निरंतर गिरावट के कारण धन के नुकसान और कतिपय अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती समस्याओं के एकजुट हो जाने से व्याप्त हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी में आई अत्यधिक तेजी से क्षमता का आधिक्य होना और मांग कमजोर होना भी इसके लिए एक अन्य महत्वपूर्ण जोरिखम है। अपस्फीति की स्थिति लगातार बने रहने से अनिश्चितता के माहौल में वृद्धि का क्षरण होता है और संसाधनों का आबंटन एवं आय के वितरण में विकृतियां आती हैं। यहां तक कि हल्की सी अपस्फीतिकारी स्थिति भी कीमतों, रोजगार, लाभ और आय में गिरावट की एक स्थायी एवं स्वतः प्रेरित अपस्फीति का घेरा बना लेती है। एक स्थायी अपस्फीतिकारी स्थिति सांकेतिक ब्याज दर पर 'शून्यकारी' प्रभाव के रूप में मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के लिए गंभीर बाधाएं पैदा कर देती है।

कुछेक एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में अपस्फीति के जोरिखम बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से जापान, हांगकांग एसएआर, और चीन के ताइवान प्रांत में। हांगकांग एसएआर में अपस्फीति का कुछ कारण तो अमरीकी डालर के साथ उसको सम्बद्ध कर देना है और अंशतः आवासीय मूल्यों में गिरावट होना है। चीन में अपस्फीति का संबंध अधिकांशतः वस्तुतः निश्चित विनिमय दर सहित उच्च उत्पादकता कारकों से प्रेरित है। विश्व व्यापार संगठन से संबद्ध प्रशुल्क की कटौती और नियंत्रित कीमतों के विनियामक दौर की वजह से भी कीमतों में गिरावट आयी है। यूरो क्षेत्र में, सीमित नीतिगत विकल्पों के होते जर्मनी को अपस्फीति का अधिकतम जोरिखम उठाना पड़ रहा है। जहां तक अमरीका का संबंध है, वहां अपस्फीति का जोरिखम तुलनात्मक रूप से कम है। समग्र रूप से, विश्व अर्थव्यवस्था अपस्फीति के मामूली से जोरिखम को झेल रही है, किंतु नीति निर्धारकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है और इनके लिए पूर्व सुरक्षोपाय के नीतिगत विकल्पों को तैयार रखें।

संदर्भ :

1. बर्नान्के, बेन एस.(2002), "डिफ्लेशन-मेकिंग श्योर इट डज नाट हैपेन हियर" बी आई एस समीक्षा 68
2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2003), "वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक" अप्रैल

बॉक्स -VI.2

विश्वव्यापी समष्टिगत आर्थिक असंतुलन

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बचत दरों में सामान्य गिरावट के कारण पिछले दो दशकों में उत्पन्न बृहत समष्टिगत आर्थिक असंतुलन ने विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसकी वजह से 1990 के दशक के प्रारंभ में विश्वव्यापी पूंजी की तंगी का भय बढ़ गया था। विश्वव्यापी बचत में अंतर को सामान्यतया प्रमुख कारक माना जाता है जिसके तहत 1980 और 1990 के दशकों में वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि हुई थी। तथापि, 1990 के दशक के अंत में, विकासशील देशों के समूह, पूंजी के वास्तविक निर्यातक साबित हुए और उन्होंने कुछेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं के बड़े और बढ़ते हुए चालू खाता के घाटे का वित्तपोषण करने में सहायता प्रदान की (सारणी)। फिर भी, बड़े पैमाने पर करंसी के पुनः समन्जन द्वारा विश्वव्यापी असंतुलन को अव्यवस्थित रूप से सुधारने के बारे में चिंताएं और भी बढ़ गयी हैं तथा अमरीकी डालर में हाल में हुए मूल्यहास ने इस चिंता को गम्भीर बना दिया है। हालांकि, बढ़ते हुए असंतुलन को विश्वव्यापीकरण की एक अभिन्न विशेषता के रूप में माना जा सकता है, फिर भी किसी भी अर्थव्यवस्था के प्रति निवल दावों के बढ़ते रहने की भी सीमाएं होती हैं जो चालू खाता के निरंतर घाटे में बने रहने में निहित हैं। ऐसे दावों की भरपाई की लागत चालू खाता घाटे को और बढ़ाती है और कतिपय परिस्थितियों में घाटे की यह स्थिति अस्थिरता का कारण बन सकती है।

आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि वास्तविक क्षेत्र समायोजन (अर्थात अमरीका जैसे घाटेवाले देशों में कम वृद्धि और अधिशेष वाले देशों में अधिक वृद्धि) के जरिए

सारणी : विश्वव्यापी चालू खाता असंतुलन

(बिलियन अमरीकी डालर)

देश / क्षेत्र	2003	2002	2001	2000	1996	1995
1	2	3	4	5	6	7
विकसित अर्थव्यवस्था	-270.4	-217.2	-187.3	-224.5	39.6	56.3
अमरीका	-576.7	-503.4	-393.4	-410.3	-117.8	-105.8
यूरो क्षेत्र	91.0	72.1	19.4	-15.1	83.9	57.2
जापान	115.5	112.8	87.8	119.6	65.7	111.4
विकासशील देश	73.6	54.9	31.1	67.1	-74.7	-95.9

स्रोत : अंमुको (2003)

बचत के असंतुलन को दूर नहीं किया गया तो हाल की अवधि में वास्तविक ब्याज दरों में आई असंतुलन की स्थिति जो विश्वव्यापी स्तर पर भरपूर वृद्धि की वजह से हुई है, पलट सकती है। हालांकि इस स्थिति से शेष विश्व की वृद्धि की संभावनाएं क्षीण हो जायेंगी, क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था काफी हद तक अमरीकी अर्थव्यवस्था की प्रगति पर निर्भर है। एशियाई क्षेत्र में, चालू खाता अधिशेष और उच्च आधिकारिक विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां विश्वव्यापी असंतुलन को प्रकट करती हैं। चूंकि मजबूत प्रगति की स्थिति अपनी जड़ें पूरे विश्व में जमाती है, इसलिए इन देशों को 1990 के दशक के प्रारंभ की चुनौती का सामना दुबारा करना पड़ सकता है, अर्थात क्या विश्वव्यापी बचत उभरते हुए बाजारों की निवेश मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और यह कि विश्वव्यापी मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से असंतुलन की कौन-सी सीमा उपयुक्त हो सकती है। सभी देशों की राजकोषीय स्थिति में स्थायी सुधार लाना ही सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि, जनसांख्यिकीय तत्व बचत दरों को निरंतर कम कर सकते हैं, यहां तक कि राजकोषीय स्थिति के लिए भी बाधक हो सकते हैं। चूंकि असंतुलन की स्थिति को किसी न किसी स्तर पर थमना है, इसलिए यह कम अव्यवस्थित होगा यदि इसके लिए अमरीकी डालर के मूल्य में मामूली-सी गिरावट करते हुए अन्य क्षेत्रों में वृद्धि की दर मजबूत करते हुए इस प्रक्रिया को बढ़ाया जाए।

संदर्भ :

1. ग्रीनस्पैन, अलन (2003), "ग्लोबल फाइनांस : इज इट स्लोइंग" बैंक दे फ्रांस इंटरनेशनल, पेरिस में मार्च 01 को मौद्रिक नीति आर्थिक चक्र और वित्तीय गणित पर दिया गया व्याख्यान।
2. हालमैन, जिल ए.(2001), "इज द लार्ज यूएस करेंट अकाउंट डेफिसिट सस्टेनेबल?" फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ कैनसास सिटी, इकॉनॉमिक रिव्यू, प्रथम तिमाही
3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2003), "वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक," अप्रैल

6.6 वर्ष 2003 में वृद्धि को बनाए रखना काफी हद तक घरेलू मांग को बढ़ाए जाने पर निर्भर करेगा, क्योंकि बाहरी मांग में तेजी आने की संभावना कम है। विश्व सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हाल में आई मंदी के संकेत, इराक में युद्ध समाप्त होने के बाद तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट विलंब से होना, अमरीकी डालर के मूल्य में भारी वृद्धि और 2003 की प्रथम तिमाही यह दर्शाती है कि हो सकता है कि वृद्धि में और अधिक सुधार की गति तेज नहीं हो पाये। अनेक एशियाई विकासशील देशों में सार्स (सीवियर एक्ज्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम) के फैल जाने के कारण और मार्च 2003 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी विश्वव्यापी चेतावनी ने पूर्व एशिया की अल्पकालीन वृद्धि की संभावनाओं को प्रभावित किया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विभिन्न अनुमान यह दर्शाते हैं कि पूर्व एशियाई देशों में वृद्धि की दर 0.1 से 0.4 प्रतिशत बिंदु तक प्रभावित हो सकती है।

6.7 विश्वव्यापी उत्पादन प्रक्रियाओं, व्यापार और वित्तीय प्रवाहों से विकासशील देशों के जुड़ जाने से उनकी घरेलू विकास की संभावनाओं पर बाहरी गतिविधियों का दबाव काफी बढ़ गया है। जहां विश्वव्यापीकरण से जुड़े ज्ञात अवसर जैसे बड़े बाजार में पहुंच, भारी मात्रा में पूंजी, उच्च प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता और बेहतर प्रौद्योगिकी इस प्रक्रिया को बनाए रखने की आवश्यकता को संगत ठहराते हैं, वहीं विश्वव्यापीकरण की लागत, विशेष रूप से आय में बढ़ती असमानता और वित्तीय संकट की अत्यधिक संवेदनशीलता प्रमुख चुनौतियां बन कर उभरी हैं (बॉक्स VI.3)।

6.8 जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि वित्तीय संकट का आना और व्यापक बाह्य प्रभाव, विश्वव्यापीकरण प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। किसी संकट के घटित होने के रोकथाम की जिम्मेदारी निश्चित रूप से राष्ट्र की होती है, जबकि ऐसे संकट यदि कभी आयें और जब कभी भी आयें तो उन्हें समाप्त करने का दायित्व इस एकीकृत

बॉक्स VI.3

विश्वव्यापीकरण - चुनौतियां और अवसर

विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया काफी असमान रही है क्योंकि बहुत से देशों में इसके फायदे और नुकसान अलग-अलग रहे हैं। विभिन्न देशों के अनुभवों और विश्वव्यापीकरण के प्रभाव के बारे में जनसामान्य की राय से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस प्रक्रिया को सभी के लिए फायदेमंद बनाया जाए। जो देश मजबूत समष्टिगत आर्थिक नीतियां अपना रहे हैं और जिनकी वित्तीय प्रणाली मजबूत एवं लचीली है वे विश्वव्यापीकरण का फायदा उठा रहे हैं। दूसरी ओर, विश्वव्यापीकृत वातावरण में खराब नीतियां अपनाने से अत्यधिक नुकसान पहुंच सकता है। विश्वव्यापीकरण के प्रतिकूल प्रभावों को रोकने के लिए सटीक नीतिगत माहौल बनाने की आवश्यकता ने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्वारा कार्यान्वित सुधार की गति, क्रम और उसकी मात्रा को प्रभावित किया है।

वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा हावी रही कि विश्वव्यापीकरण के प्रतिकूल प्रभावों से कैसे निपटा जाए। 1980 से विश्वव्यापीकरण प्रक्रिया के दौरान गरीबी और असमानता के संकेतकों के परीक्षण से पांच महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां पाई गई हैं : (क) गरीब देशों के विकास में गति आना, (ख) विश्व में निर्धन व्यक्तियों की संख्या में काफी गिरावट, (ग) विश्वव्यापी असमानता में मामूली-सी गिरावट, (घ) राष्ट्रों के भीतर असमानता बढ़ने की सामान्य प्रवृत्ति न होना, और (ङ) पूरे विश्व में बढ़ती हुई वेतन असमानता (डालर, 2002)। इन निष्कर्षों पर प्रश्न इस आधार पर उठाया गया है कि वर्तमान सांख्यिकी उतनी सक्षम नहीं है कि विश्वव्यापी गरीबी प्रवृत्ति का विश्वासपूर्वक कोई जवाब दे सके। वैकल्पिक प्रणालियां बहुत अच्छी तरह से यह दर्शा सकती हैं कि विश्वव्यापी असमानता बढ़ रही है या नहीं और यह भी कि - पश्चिमी देशों और शेष देशों के बीच समग्र आय का अंतर बढ़ रहा है। तथापि, भल्ला (2002) के अनुसार, ऐसा कोई कल्याणकारी संकेतक नहीं है जिसके अनुसार यह कहा जा सके कि पिछले 20 वर्षों में विश्व अर्थव्यवस्था ने बेहतर कार्य नहीं किया है।

आय असमानता की तरह ही, वित्तीय खुलेपन के साथ जुड़े जोखिम भी नीति निर्धारण में प्रमुख चिंता का विषय रहे हैं, और वित्तीय खुलेपन के प्रभावों के संबंध में परस्पर विरोधी अनुभवजन्य निष्कर्ष होने के कारण यह मुद्दा काफी संदिग्ध हो गया है। वित्तीय विश्वव्यापीकरण से पूंजी का आना बढ़ सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि इससे विकास की दर बढ़ जाएगी। यह मूल्यांकन इस आधार पर संगत हो सकता है कि विभिन्न देशों में प्रति व्यक्ति आय में पाया जाने वाला अंतर यह जरूरी नहीं है कि वह पूंजी-श्रम अनुपात (जिस पर वित्तीय विश्वव्यापीकरण का प्रभाव पड़ सकता है) के अंतर से उपजा हो, बल्कि वह कुल कारक उत्पादकता (जो वित्तीय विश्वव्यापीकरण पर निर्भर होने के बजाय घरेलू कारकों जैसे संचालन, कानून व्यवस्था, संपत्ति अधिकार

के प्रति समादर पर निर्भर हो सकते हैं) के अंतर से उपजा हो। इसमें ‘‘प्रारंभिक प्रभाव’’ भी हो सकता है जिससे केवल उन्हीं देशों को वित्तीय विश्वव्यापीकरण से फायदा हो सकता है जो किसी एक स्तर तक आत्मसात करने की क्षमता रखते हैं। वृद्धि के बारे में वित्तीय विश्वव्यापीकरण के प्रभाव के संबंध में 14 अनुभवजन्य अध्ययनों की तुलना करने से पता चलता है कि केवल तीन अध्ययन ही वृद्धि पर वित्तीय विश्वव्यापीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताते हैं।

पूर्वी एशियाई संकट के बाद से वित्तीय खुलेपन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय राय में काफी परिवर्तन आया है। कहीं तो इसके बारे में खुले तौर पर भारी विरोध जताया गया है, और प्रायः इसके निष्कर्ष ब्रेटनवुड संस्थाओं की अर्धवार्षिक बैठकों से निकलकर बाहर की दुनिया में व्यक्त किये गये हैं। तथापि, अभी तक इस प्रक्रिया को कोई बहुत बड़ा धक्का नहीं लगा है। इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जोखिमों की रोकथाम करते हुए विश्वव्यापीकरण के फायदे उठाए जाएं। विश्वव्यापीकरण प्रक्रिया सभी के लिए बेहतर हो सकती है, यदि विकसित अर्थव्यवस्थाएं अपने बाजारों को विकासशील देशों के लिए खोल दें और एक देश से दूसरे देश में श्रमशक्ति के आवागमन को अधिक सहज बनाने के लिए अपनी आप्रवासन नीतियों को उदार बना दें। यह भी मान्यता है कि विश्वव्यापीकरण प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए किसी देश को अपनी आत्मसात करने की क्षमता को बढ़ाना होगा। यह अपेक्षा श्रमशक्ति की प्रकृति, घरेलू वित्तीय बाजारों के विस्तार, समष्टिगत आर्थिक नीतियों और संचालन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है।

संदर्भ:

1. भल्ला, सुरजीत एस. (2002), ‘‘इमैजिन देयर इजोनो कंट्री : पावर्टी, इन्इक्वैलिटी एंड ग्रोथ इन द एरा आफ ग्लोबलाइजेशन,’’ इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इकॉनॉमिक्स ।
2. डॉलर, डेविड (2002), ‘‘ग्लोबल इकॉनॉमिक इंटीग्रेशन एंड ग्लोबल इन्इक्वैलिटी,’’ 27-28 मई को जी-20 कार्यशाला में प्रस्तुत पेपर।
3. जी-20 (2002), ‘‘ग्लोबलाइजेशन, लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड इन्इक्वैलिटी,’’ रिजर्व बैंक ऑफ आस्ट्रेलिया और आस्ट्रेलियन ट्रेजरी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया सम्मेलन अंक।
4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2002), *वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक* का अध्याय III, सितंबर ।
5. प्रसाद, इ. एंड एस.जे.वेइ (2003), ‘‘इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल ग्लोबलाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज,’’ सम एम्पेरिकल एविडेंस, अंमुको, फरवरी ।

और परस्पर-निर्भर विश्व के समस्त देशों को दिया जाना चाहिए। इस चिंता ने एक उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना की खोज को प्रोत्साहित किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट से बचाव के उपायों और प्रस्तावित संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकारी ऋण पुनर्संरचना प्रणाली (एसडीआरएम) पर अधिक जोर दिया जा रहा है ताकि वित्तीय संकट बढ़ने की संवेदनशीलता को नियंत्रित किया जा सके (बॉक्स VI.4)।

भुगतान संतुलन

6.9 वर्ष 2002-03 के दौरान भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति में, प्रत्येक तिमाही में समग्रतः अधिशेष रहते हुए काफी सुधार हुआ है। व्यापारिक माल और अदृश्य मर्दों के भारी निर्यात होने से चालू खाता अधिशेष की स्थिति में आ गया है, जबकि पिछले वर्ष आयात मांग में कमी के कारण चालू खाते में अधिशेष बहुत ही मामूली-सा था। अर्थव्यवस्था में व्यापार योग्य मर्दों हेतु सहभागिता की शर्तों

बॉक्स VI.4

सरकारी ऋण पुनर्गठन प्रणाली में हुई प्रगति

1990 के दशक में बार-बार वित्तीय संकट आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समुदाय ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना के कतिपय घटकों में विशेष रूप से संकट-बचाव के क्षेत्र में, सुधार लाने में काफ़ी प्रगति की है। तथापि, संकट संबंधी प्रस्ताव के क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उपप्रबंध निदेशक, अन्ने क्रुयेगेर द्वारा एक उपयुक्त सरकारी ऋण पुनर्गठन प्रणाली (एसडीआरएम) की स्थापना किए जाने की पहल पर हाल में हुई बहस ने इस मामले में बेहतर प्रगति की काफ़ी उम्मीदें पैदा कर दी हैं। एसडीआरएम के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अद्यतन स्थिति की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:

- पुनर्गठन अधिकांशतः ऋणी सरकार और उनके अधिकांश ऋणदाताओं के मध्य पुनर्गठन की शर्तों पर एक करार करवाएगी जो सभी ऋणदाताओं पर बाध्यकारी होगा।
- तथाकथित 'हाचपाँच' नियम के अंतर्गत विघटनकारी मुकदमे के निवारण (भय दिखाकर) का प्रावधान जिसके तहत ऋणदाता द्वारा मुकदमा करके वसूली गई किसी रकम को अनुमोदित पुनर्गठन करार के अंतर्गत शेष दावे की राशि में से घटा दिया जाएगा।
- ऋणदाता के हितों की रक्षा
- नए वित्तीयन को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिकता वित्तपोषण

सदस्य देशों में एसडीआरएम की डिजाइन, कवरेज, कार्यान्वयन और प्रणालीगत मामले तथा विभिन्न ऋणदाताओं के समूहों से लिए गए उदाहरण पर आम सहमति न बन पाने से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एसडीआरएम की स्थापना का प्रस्ताव अधर में लटक गया है। इसमें कई अनसुलझे मुद्दे बकाया हैं : जैसे ऋणी द्वारा एसडीआरएम की एकपक्षीय क्रियाशीलता की अनुमति देना, ऋणदाता के मुकदमे पर स्थगन के प्रवर्तन से संबंधित मानदण्ड, ऋण की व्याप्ति और घरेलू एवं बाह्य ऋणदाता के बीच समानता सुनिश्चित करना।

एसडीआरएम के संबंध में निजी क्षेत्र, विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करते हुए कि विवाद प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को प्राप्त वरिष्ठ ऋणदाता का दर्जा और उसका ऋणियों (जो अंमुको के सदस्य हैं) के प्रति तथाकथित पक्षपातपूर्ण रवैया इनके बीच हितों के टकराव के प्रति आशंका व्यक्त करता रहा है। निजी क्षेत्र ऋण के नैतिक पतन के प्रति भी चिंतित है और इसलिए विशिष्ट ऋण संकट को समाप्त करने के लिए बाजार प्रणाली पर अधिक भरोसा करता है। बाजार प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य करे, इसके लिए बाण्ड संविदा में सामूहिक कार्रवाई की शर्तें (सीएसी) जोड़ते हुए सामूहिक रूप से कार्रवाई करने की समस्या हल की जानी चाहिए। सामूहिक कार्रवाई की समस्या इसलिए पैदा हुई, क्योंकि ऋण देने वाला व्यक्ति अडिग रहा अर्थात् इस आशा से कि वह मूल संविदा शर्तों पर भुगतान की वसूली कर लेगा। उसने स्वैच्छिक रूप से पुनर्गठन प्रक्रिया में भाग लेने से मना कर दिया, हालांकि यदि वे इस पुनर्गठन के लिए सहमत हो जाएं तो ऋणदाता समूह को कहीं बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी और यह उनके आस्तित्व पर ऋण-सीमा घटाने के प्रति सहायक होगी।

अमरीकी ट्रेजरी ने फरवरी 2002 में विभिन्न सीएसी को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सितंबर, 2002 में सीएसी से संबंधित जी-10 कार्यदल रिपोर्ट ने श्रेष्ठ बाण्डों के लिए सीएसी की प्रमुख विशेषताएं निर्दिष्ट की थीं। अप्रैल 2002 में, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एसडीआरएम और सीएसी पर आधारित "द्विमार्गी" दृष्टिकोण की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया। बाजार आधारित दृष्टिकोण एसडीआरएम की तुलना में अधिक लचीला है, क्योंकि यह प्रत्येक मामले की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए ऋण-संकट के मामले-दर-मामले हेतु उपयुक्त होता है। इसकी खामी यह है कि यह ऐसे मौजूदा निर्गमों की समस्या का निदान नहीं करता है जिनमें सामूहिक कार्रवाई की शर्तें (सीएसी) शामिल नहीं हैं। दूसरी समस्या यह है कि सीएसी में उपबंधों के समूहन का प्रावधान नहीं है अर्थात् ऐसे उपबंध जो श्रेष्ठ ऋणी सरकार के समस्त निर्गमों के बाण्डों का समूहन कर सकें ताकि ऋणदाताओं के बीच इक्विटी प्रदान की जा सके और साथ ही ऐसे ऋणदाताओं को मुकदमेबाजी तथा विघटनकारी क्रियाओं से रोक सके जिनके पास किसी एक बाण्ड निर्गम का अधिकांश हिस्सा है।

एसडीआरएम और सीएसी के संबंध में हाल में हुई बहस का एक सकारात्मक पहलू यह रहा है कि बाजार सहभागियों और ऋणी सरकारों की सीएसी में दिलचस्पी बढ़ने लगी है। यूरोपियन यूनियन ने अपने देशों के सरकारी बाण्डों के निर्गमों में सीएसी को शामिल करने की पहल पर सहमति व्यक्त करके ऋणी के प्रथम प्रवर्तक की समस्या खत्म कर दी है। हाल में मेक्सिको और ब्राजील ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय बाण्ड निर्गमों में भी सीएसी को शामिल कर लिया है और इस बात को झूठा साबित कर दिया है कि इसके पहले प्रवर्तक को अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम की समस्या का सामना करना पड़ेगा। आइएमएफसी ने अप्रैल 2003 में आयोजित इसकी बैठक में यह खुलासा किया है कि एसडीआरएम को स्थापित करने के लिए और प्रयास करना सार्थक नहीं है, किंतु ऐसे मुद्दों पर कार्य जारी रहना चाहिए जिनकी वित्तीय संकट के उपयुक्त प्रस्तावों के प्रति सामान्य प्रासंगिकता हो।

संदर्भ :

1. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2003) : "आइएमएफ बोर्ड डिस्कसेस इकॉनॉमिक पॉलिसी इश्यूज अराइजिंग इन द कान्टेक्स्ट ऑफ ए सावेरिन डेट रीस्ट्रक्चरिंग", पब्लिक इन्फर्मेशन नोटिस (पीआइएन), 2 अप्रैल; "आइएमएफ बोर्ड डिस्कसेस पासिबल फीचर्स ऑफ ए सावेरिन डेट रीस्ट्रक्चरिंग मेकानिज्म" पीआइएन, 3 अप्रैल
2. क्रुयेगर, ए (2001) : "इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर फार 2002 : अ न्यू अप्रोच टु सावेरिन डेट रीस्ट्रक्चरिंग", अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन, डीसी.
3.(2003) : "द नीड टु इम्पूव द रेजोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस: ऐन इमरजिंग कनसेंसस ?" अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन, डीसी.

में बढ़ता हुआ खुलापन काफ़ी हद तक निर्यात की स्थिति पर निर्भर करता है। चालू प्राप्तियों में स्वस्थ वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमताओं एवं आयात हेतु क्रय शक्ति पर हितकारी प्रभाव डालता है। स्थिर

अनिवासी जमाराशियों द्वारा समर्थित बैंकिंग पूंजी के संचलन को बहुपक्षीय ऋण की भारी पूर्व अदायगी के बावजूद उच्चतर निवल पूंजी प्रवाह के अंतर्गत लाया गया है। (सारणी 6.1)।

सारणी 6.1 : भुगतान संतुलन : प्रमुख संकेतक

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद/संकेतक	2002-03	2001-02	2000-01	1999-2000	1990-91
1	2	3	4	5	6
i) व्यापार शेष	-12,474	-12,703	-14,370	-17,841	-9,437
ii) अदृश्य, निवल	16,182	13,485	10,780	13,143	-243
iii) चालू खाता शेष	3,708	782	-3,590	-4,698	-9,680
iv) पूंजी खाता	12,638	10,573	10,018	10,444	7,056
v) समग्र शेष #	16,980	11,757	5,856	6,402	-2,492
vi) विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (+ वृद्धि, - कमी) (मूल्यन परिवर्तनों को छोड़कर)	-16,980	-11,757	-5,830	-6,142	1,278
संकेतक (प्रतिशत में)					
1. व्यापार					
i) निर्यात/सदेउ	10.4	9.3	9.8	8.4	5.8
ii) आयात/सदेउ	12.8	12.0	12.9	12.4	8.8
iii) व्यापार वृद्धि का आय स्वरूप	..	1.6	18.2	3.4	0.1
iv) निर्यात मात्रा वृद्धि	..	3.9	23.9	15.5	11.0
2. अदृश्य मदे					
i) अदृश्य प्राप्तियां/सदेउ	8.4	7.7	7.6	6.8	2.4
ii) अदृश्य भुगतान/सदेउ	5.3	4.9	5.2	3.8	2.4
iii) अदृश्य (निवल)/सदेउ	3.1	2.8	2.4	3.0	-0.1
3. चालू खाता					
i) चालू प्राप्तियां @/सदेउ	18.7	16.9	17.3	15.1	8.0
ii) चालू प्राप्तियां वृद्धि @	17.7	2.4	17.6	12.9	6.6
iii) चालू प्राप्तियां @/चालू भुगतान	103.6	100.5	95.3	93.0	71.5
iv) चालू खाता शेष/सदेउ	0.7	0.2	-0.8	-1.1	-3.1
4. पूंजी खाता					
i) विदेशी निवेश/सदेउ	1.1	1.7	1.5	1.2	0.0
ii) विदेशी निवेश/निर्यात	10.6	18.1	15.1	13.8	0.6
5. अन्य					
i) ऋण-सदेउ अनुपात	20.0	21.0	22.4	22.2	28.7
ii) ऋण चुकोती अनुपात	14.7	13.9	17.2	16.2	35.3
iii) देयता चुकोती अनुपात	15.7	14.9	18.4	17.0	35.6
iv) आरक्षित निधियों का आयात कवर (महीनों में)	13.8	11.3	8.6	8.2	2.5
# भूलचूक सहित	.. उपलब्ध नहीं		@ अधिकृत अंतरण को छोड़कर		

वाणिज्यिक व्यापार

6.10 वर्ष 2002 में भारत, विश्व व्यापार में धीमे सुधार के बावजूद अग्रणी निर्यातक राष्ट्रों में चीन के बाद विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई निर्यातक अर्थव्यवस्था में दूसरे स्थान पर रहा है। निर्यात में हुई 19.2 प्रतिशत की वृद्धि वर्ष 2002-03 के लिए निर्धारित 12 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी अधिक है। इससे यह परिलक्षित होता है कि व्यापार की मात्रा और उसकी स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार द्वारा हाल के वर्षों में निर्यात उत्पादों और बाजार विशाखीकरण के लिए की गई विभिन्न नीतिगत पहल निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में सहायक रही है (बॉक्स VI.5)।

6.11 वर्ष 2002-03 के दौरान निर्यात वृद्धि का आधार सभी पण्य समूहों के निर्यात और विभिन्न गंतव्य स्थानों को निर्यात की दृष्टि से व्यापक था। प्राथमिक उत्पादों और विनिर्मित वस्तुओं दोनों में तीव्र

वृद्धि दर्ज की गई (सारणी 6.2 और परिशिष्ट सारणी VI.4)। प्राथमिक उत्पाद निर्यातों में वृद्धि के प्रमुख स्रोत अयस्क और खनिज, चावल और समुद्री उत्पाद थे। अंतर्राष्ट्रीय धातु मूल्यों में सुधार से कच्ची धातुओं और खनिज के निर्यात में को लाभ पहुँचा। प्रमुख कृषि पण्यों में अनाजों (चावल और गेहूँ) के निर्यात ने काफी वृद्धि दर्ज की, क्योंकि अमरीका, कनाडा और आस्ट्रेलिया में भयंकर सूखे के कारण पूरे विश्व में इसकी आपूर्ति की किल्लत थी। जहां तंबाकू और समुद्री उत्पादों के निर्यात में तीव्र सुधार आया, वहीं चाय और कॉफ़ी के निर्यात में कमी आती रही। इन निर्यात मदों के निष्पादन पर भारत के निर्यातों में संरचनागत परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चाय और कॉफ़ी का महत्त्व भारत के कुल निर्यात की दृष्टि से और विश्व बाजार में भारत के निर्यात की दृष्टि से कम हुआ है। संरचनागत बाधाओं ने भी विशेषतया, चाय के मामले में इसके निर्यात को प्रभावित किया है। हाल के वर्षों में मंद घरेलू मांग और पारंपरिक

बॉक्स VI.5

निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के बदलते स्वरूप

विश्व के व्यापार स्वरूपों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। कई विकासशील देश और अर्थव्यवस्थाएं संक्रमण की स्थिति में विश्वव्यापी व्यापार प्रतिस्पर्धा से प्रत्यक्षतः लाभान्वित हुई हैं। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी की मुख्य भूमिका रही है। विशिष्ट वास्तविकताओं से कई देशों ने उन उत्पादों में वृद्धि दर्ज की है जिसके व्यापार के लिए उनके अपने देश में सक्रिय और स्पष्ट खरीदार मौजूद हैं। निर्यातक फर्म के निकट आपूर्तिकर्ताओं और सहायक उद्योगों की फर्मों की मौजूदगी भी प्रतिस्पर्धा लाभ मिलने का प्रमुख स्रोत है। सतत प्रतिस्पर्धा-लाभ के सैद्धांतिक आधार को जानना और उसे मजबूत बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से आर्थिक विकास में गति लाने के माध्यम के रूप में निर्यात को तेजी से बढ़ाए जाने की आवश्यकता के संदर्भ में।

निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का आशय किसी देश की विश्व बाजार में अपनी सहभागिता बढ़ाने की योग्यता से है और जो मूल्य और मूल्येतर कारकों पर निर्भर है। पारंपरिक रूप से व्यापार किए जानेवाले भागीदार की तुलना में किसी देश की अपनी उत्पादकता में वृद्धि एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। हाल के साहित्य में इस बात का तीव्र अनुभव किया गया है कि स्थिर उत्पादन क्षमताओं की तुलना में सक्रिय कारकों की मुख्य भूमिका होती है। अन्य बातों के साथ-साथ नई प्रौद्योगिकी, उत्पादन प्रक्रिया के नए तरीके, भागीदार से व्यापार करने अथवा प्रतिस्पर्धी देश को ध्यान में रखकर बनाई गई व्यापार नीतियों के साथ उत्पादन प्रक्रिया में हुए संरचनात्मक परिवर्तन ने तथा बहुपक्षीय व्यापारिक नियम ने भी प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव डाला है। विनिमय दर को प्रतिस्पर्धात्मकता मूल्य का महत्वपूर्ण निर्धारक माना जाता है। मूल्येतर कारक जैसे उत्पाद की गुणवत्ता, ब्राण्ड का नाम, पैकेजिंग, सुपुर्दगी और बिक्री के बाद की सेवाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण कारक हैं।

निर्यात कार्यों के प्रति नीतिगत परिवर्तनों की भूमिका का उल्लेख कर पाना आसान नहीं है। तथापि, यह कहना उपयुक्त होगा कि विश्वव्यापी विकास ने जो अवसर पैदा किए हैं उनका इस्तेमाल, उद्योग और व्यापार का उदारीकरण करते हुए नीतिगत क्षेत्र में परिवर्तन करके, प्रतिबंधों अथवा विनियमों को हटाकर उपयुक्त रणनीति अपनाते हुए निर्यात संवर्धन, निर्यात संबंधी प्रोत्साहनों को अधिक लोगों तक पहुंचा करके, उत्पाद अथवा बाजार विशेष योजनाओं की घोषणा और प्रक्रियागत सरलीकरण करके किया गया। भारत में किये गये अध्ययन यह दर्शाते हैं कि बढ़ती हुई स्पर्धा से मूल्य सीमांत लागत की वृद्धि में कमी आयी है और फर्मों अधिकांशतः विलयन एवं अधिग्रहणों, आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने और अनुसंधान एवं विकास के लिए अधिकाधिक प्रयासों पर बल दे रही हैं। इस बात पर व्यापक सहमति है कि 1980 के दशक के मध्य से भारतीय विनिर्माण के क्षेत्र में कुल उत्पादन उत्पादकता वृद्धि ने पलटा खाया है जिसका श्रेय अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार नीतियों के पुनर्विन्यास और बेहतर मूलभूत सुविधाओं के निष्पादन को जाता है। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि विशेषतया 1990 के दशक के उत्तरार्ध में इनपुट सामग्री के इस्तेमाल की दक्षता बढ़ी है। प्रक्रियागत अथवा प्रशासनिक असुविधाओं के कारण निर्यातकों की कारबार-लागतों में गिरावट हुई है, हालांकि निरपेक्ष रूप से ये लागतें अभी भी ऊंची बनी हुई हैं।

विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा स्वतंत्रता के समय 2 प्रतिशत था जो 1980 के दशक के मध्य में 0.5 प्रतिशत तक नीचे गिरने के बाद वर्ष 2002 में बढ़कर 0.8 प्रतिशत हो गया है। पिछले अध्ययनों से पता चलता है कि पूर्वी एशियाई देशों के निर्यात में तीव्र संरचनागत परिवर्तनों के बिल्कुल विपरीत भारत की पण्य संरचना 1990 दशक के मध्य तक लगभग स्थिर बनी रही। तथापि, हाल के वर्षों के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत के निर्यात की पण्य-संरचना प्रौद्योगिकी प्रधान उच्च मूल्य विनिर्माण की ओर उन्मुख हो गई है और पारंपरिक स्वरूप की श्रम प्रधान वस्तुओं के विनिर्माण एवं कच्चे मालों के निर्यात से विमुख हुई है। हालांकि, अभी से इस नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा कि आगे नाटकीय परिवर्तन होंगे। निर्यात का गंतव्य स्वरूप विकासशील देशों और ओपेक समूह के देशों में बदल रहा है। बाजार का फैलाव काफी बढ़ा हो गया है। विश्व परिदृश्य में भारत की प्रतिस्पर्धा स्थिति थोड़ी सी बढ़ी है। वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम की विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट के अनुसार 'विकास प्रतिस्पर्धात्मकता स्थान' में भारत का स्थान 1999 के 52वें स्थान की बजाए वर्ष 2002 में 48वां स्थान हो गया है। कई प्रमुख क्षेत्रों में भारत को विशिष्ट श्रेष्ठता प्राप्त है। वर्ष 2002 में भारत का 'विदेशी प्रौद्योगिक लाइसेंसिकरण प्रचलन' में पहला स्थान, 'वैज्ञानिकों और अभियंताओं की उपलब्धता' में दूसरा 'ऋण तक पहुंच' में पांचवां 'स्थानीय प्रतिस्पर्धा' में तीव्रता 'में सातवां और 'ब्याज दर स्प्रेड' में ग्यारहवां स्थान है। विश्वव्यापी व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता के स्वरूप के संबंध में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन के मूल्यांकन ये दर्शाते हैं कि 1985-2000 की अवधि के दौरान निर्यात बाजार में 20 प्रमुख बड़ी हिस्सेदारी वाले समूह में भारत का स्थान समस्त निर्यात में चौदहवां, संसाधन आधारित विनिर्माण में पांचवां और औसत प्रौद्योगिकी विनिर्माण में सत्रहवां था।

संदर्भ :

1. बसंत, राकेश (2000) : "कापोरिट रिस्पांस टु इकॉनॉमिक रिफार्म्स" *इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली*, 4 मार्च
2. भारतीय निर्यात आयात बैंक (2003) : *ट्रांज़ैक्शन कास्ट्स ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स* : अ रिव्यू, वर्किंग पेपर शृंखला, पेपर सं.4
3. मरजीत, एस.एंड ए. राय चौधुरी (1997) : *इंडियाज एक्सपोर्ट्स - ऐन एनालिटिकल स्टडी*, आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस।
4. मोहन राकेश (2000) : "स्माल स्केल इंडस्ट्री पॉलिसी इन इंडिया : अ क्रिटिकल इवैलुएशन" अन्ने ओ.कुरुयेगर (सं.) : "इकॉनॉमिक पॉलिसी रिफार्म्स एंड द इंडियन इकॉनॉमी", ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस
5. पोर्टर माइकल इ (1990) : *द काम्पेटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशन्स*, मैकमिलन, लंदन
6. अंकटाड (संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन) (2002): *वर्ल्ड इनवेस्टमेंट रिपोर्ट 2002 : ट्रांज़ैक्शनल कापोरिशंस एंड एक्सपोर्ट काम्पेटिटिवनेस*, यूनाइटेड नेशंस, न्यूयार्क

चाय निर्यातकों द्वारा पुरानी चाय की कुल न्यूनतर खरीद के कारण भारतीय चाय उद्योग को घटती हुई कीमतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी ओर कृषि के विशाखीकरण और व्यापार नीतियों को

प्रोत्साहन मिलने से संसाधित मदों जैसे- सब्जियों, फलों और रसों, पुष्प उत्पादों, मांस और मांस से बने पदार्थों और समुद्री उत्पादों का महत्व बढ़ गया है।

सारणी 6.2 : चुनिंदा पण्यों में भारत का निर्यात

प्रतिशत अंतर

पण्य समूह	2002-03 अ	2001-02
1	2	3
I. प्राथमिक उत्पाद	16.0	0.5
क. कृषि एवं संबद्ध उत्पाद में :	8.7	-1.2
जिसमें से		
1. चाय	-7.0	-7.9
2. कॉफी	-12.3	-11.5
3. चावल	66.5	3.7
4. तंबाकू	22.5	-10.8
5. समुद्री उत्पाद	11.7	-11.3
ख. अयस्क और खनिज	50.5	9.5
II. विनिर्मित वस्तुएं	14.9	-2.8
जिसमें से		
क. चमड़ा और विनिर्मित उत्पाद	-6.4	-1.8
ख. रासायनिक और संबंधित उत्पाद	16.2	2.8
ग. इंजीनियरिंग माल	20.6	2.0
घ. वस्त्र उद्योग	9.3	-9.3
ड. रत्न और आभूषण	21.2	-1.1
च. हस्तशिल्प	31.3	-17.0
छ. कालीन	-2.6	-12.3
III. पेट्रोलियम उत्पाद	14.3	12.0
IV. अन्य	168.1	-2.7
कुल निर्यात	19.2	-1.6

अ : अन्तिम

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय (डीजीसीआइएंडएस)

6.12 मूल्यवृद्धि वाली विनिर्मित वस्तुएं जैसे रत्न और आभूषणों इंजीनियरिंग वस्तुओं, रासायनिक और संबंधित उत्पादों तथा वस्त्र उद्योग निर्यात में विस्तार हुआ है (सारणी 6.2)। रत्न और आभूषणों के निर्यात में तीव्र वृद्धि, जिसकी मांग आय-लोच पर आधारित है, अमरीका, बेलजियम, इजरायल और सिंगापुर के बाजारों में आयी बेहतर स्थिति के कारण हुई है। इन निर्यातों को समर्थित नीतिगत

उपायों जैसे सादे और मशीन से जड़े आभूषणों के निर्यात से संबंधित मूल्य-वृद्धि के मानदण्डों में नरमी, अपरिष्कृत हीरे हेतु लाइसेंस व्यवस्था की समाप्ति और अपरिष्कृत हीरों के आयात पर शून्य सीमा शुल्क से भी लाभ पहुंचा है। 'परिवहन उपकरणों' और 'लोहा एवं इस्पात' क्षेत्र से निकली इंजीनियरिंग वस्तुओं के उच्च निर्यात से विश्वव्यापी मांग तथा उत्पादन प्रक्रियाओं में अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया में सुधार परिलक्षित होता है। वस्तुतः औद्योगिकीकृत देशों द्वारा इनको खपत किए जाने से मुख्य रूप से अमरीका, जर्मनी और इटली ने परिवहन उपकरणों के निर्यात के विस्तार को तेज किया है। लोहा और इस्पात के मामले में निर्यात वृद्धि मुख्यतः उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं, जैसे चीनी तेइपेइ, कोरिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल में पाई गई है, जो घरेलू उत्पादन में हुई वृद्धि से है, तथापि चमड़ा और चमड़ा उत्पाद तथा कालीन के निर्यातों में कमी हुई है।

6.13 उत्पाद विशाखीकरण के अलावा, पिछले कुछ वर्षों के दौरान भारत की निर्यात रणनीति ने कतिपय पहलों के साथ जैसे- 'लैटिन अमरीकी देशों पर ध्यान केंद्रित करना' (यह प्रयास नवंबर 1997 से प्रारंभ होकर मार्च 2003 तक चलेगा) तथा 'अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित करना' (31 मार्च, 2002 को प्रारंभ) बाजार विशाखीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष 2002-03 के दौरान प्रमुख बाजारों जैसे अमरीका, यूरो क्षेत्र, अन्य विकासशील देशों एवं तेल उत्पादक एवं निर्यातक देशों को किए गए निर्यात में काफी वृद्धि दर्ज की गई। विकासशील देशों के समूह में, निर्यात विस्तार के अत्यधिक महत्त्वपूर्ण स्रोत चीन (जहां निर्यात लगभग दुगुना हुआ) और सिंगापुर (बॉक्स VI.6) थे। लैटिन अमरीकी देशों को किए जानेवाले निर्यात में भी वृद्धि हुई है। तेल और पेट्रोलियम निर्यात देश समूह में निर्यात विस्तार का मुख्य स्रोत संयुक्त अरब अमीरात था।

बॉक्स VI.6

चीन के साथ भारत का व्यापार

भारत और चीन के बीच सरकारी तौर पर द्विपक्षीय व्यापार 1978 में प्रारंभ हुआ। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार विशेष रूप से फरवरी 2000 में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद से काफी बढ़ गया है, जिसके अंतर्गत चीन ने 24 मदों पर शुल्क की छूट देने पर सहमति दी है और जो मुख्यतया कृषि, कृषि उत्पाद और समुद्री पण्यों से संबंधित हैं। इस समझौते में बैंकिंग और बीमा मानदण्डों में ढील देने के अलावा, कृषि उत्पादों के टेरिफ दर कोटा को युक्तिपरक बनाना, फार्मास्युटिकल उद्योग खोलने और भारतीय पण्यों को चीन में सहजता से निर्यात करने के लिए पादप स्वास्थ्य मानदण्डों को सरल बनाना भी शामिल है। अन्य प्रमुख नीतिगत पहल में सूचना प्रौद्योगिकी और श्रम के क्षेत्र में इस्पात और सहयोग के संबंध में एक संयुक्त कार्यसमूह गठित करने के लिए वर्ष 2000 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना शामिल है। वर्ष 1998-99 से 2002-03 के दौरान भारत से चीन को किया गया निर्यात अमरीकी डालर में 46.4 प्रतिशत वार्षिक की औसत दर से बढ़ा है, जबकि चीन से किए गए आयात में वार्षिक औसत वृद्धि 26.2 प्रतिशत हुई है जो उसी अवधि में

भारत के समग्र निर्यात और आयात में हुई वृद्धि से कहीं अधिक है। केवल वर्ष 2002-03 के दौरान, भारत से चीन को किया गया निर्यात दुगुने से अधिक हो गया है, जिसने चीन के साथ व्यापार घाटे को कम किया है (सारणी)।

सारणी : चीन के साथ भारत का व्यापार

(मिलियन अमरीकी डालर)

	निर्यात	आयात	व्यापार शेष
1	2	3	4
1990-91	18	35	-17
1998-99	427	1,097	-670
1999-00	539	1,288	-749
2000-01	831	1,502	-671
2001-02	952	2,036	-1,084
2002-03	1,961	2,783	-821

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय (जारी...)

भारत से चीन को किए गए निर्यात में आई यह तेजी मुख्यतया मध्यम और उच्च दर्जे की प्रौद्योगिकी के उत्पादों का निर्यात करने से आई है। भारत से चीन को निर्यात की गई मुख्य मर्दे इंजीनियरिंग वस्तुएं, कच्चा लोहा और रसायन संबंधी उत्पाद हैं। वर्ष 2002-03 में भारत से चीन को किए गए निर्यात में 70 प्रतिशत से अधिक निर्यात इन्हीं तीन उत्पाद समूहों का था। जहां तक आयात का संबंध है, मुख्य आयात मर्दों के रूप में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात किया जा रहा है। इससे अन्य मुख्य आयातित मर्दों जैसे रसायन, कोयला, कोक तथा ब्रिकेट के आयात में कमी आई है (सारणी)।

सारणी : चीन को/से किए गए भारत के प्रमुख निर्यात और आयात

(कुल निर्यात/आयात के प्रति प्रतिशत)

मद/समूह	2002-03	2001-02	2000-01	1997-98
1	2	3	4	5
निर्यात				
इंजीनियरिंग वस्तुएं	31.3	7.0	12.4	4.4
कच्चा लोहा	20.4	21.7	15.6	13.6
रसायन और संबंधित उत्पाद	19.8	32.1	29.7	10.4
अन्य अयस्क और खनिज	6.3	11.9	8.8	6.2
समुद्री उत्पाद	5.4	8.9	13.9	16.0
आयात				
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं	27.8	18.9	16.3	9.7
रसायन	13.3	14.8	15.2	22.1
टेक्सटाइल यार्न, फैब्रिक्स, निर्मित वस्तुएं	7.6	6.2	5.2	4.9
कोयला, कोक और ब्रिकेट	6.0	12.9	17.4	16.6
औषधीय और फार्मास्युटिकल उत्पाद	5.2	5.2	4.7	5.9

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय

हाल की इस तेज वृद्धि के होते हुए भी, भारत का निर्यात अभी चीन के कुल आयातों के एक प्रतिशत से भी कम है (वर्ष 2001 में 0.8 प्रतिशत)। चीन द्वारा आयात और खनिज उत्पाद, लोहा और इस्पात, कार्बनिक रसायन, निर्यात वस्तु समूह की महत्वपूर्ण मर्दे हैं। इस प्रकार, चीन का बाजार भारतीय निर्यातकों को भारी संभाव्यता उपलब्ध कराता है। दिसंबर 2001 में चीन के विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन जाने, घरेलू बाजार के और अधिक विदेशी प्रतिस्पर्धा और वाणिज्यिक मौजूदगी के लिए खोल देने से भारतीय निर्यातकों के लिए अच्छे अवसर पैदा हो गए हैं। इस बात की संभावना है कि विश्व व्यापार संगठन और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर दोनों अपने-अपने हित को बढ़ाना चाहें तथापि, चीन का सबसे बड़ा निर्यात बाजार (अर्थात अमरीका, हांगकांग, जापान, यूरोपियन यूनियन और कोरिया) भारत के लिए भी प्रमुख निर्यात बाजारों में से है, भारत को वस्त्र, कपड़ा, चमड़ा और चमड़ा उत्पाद तथा हल्की मशीनरी के विदेशी निर्यात बाजार में चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है।

सेवा क्षेत्र की सहायता से व्यापार को और भी बढ़ाया जा सकता है यदि भारत और चीन दोनों देशों के बीच डिजिटल विभाजन को भरने और इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली का अधिकतम उपयोग करने के लिए रणनीति विकसित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी (क्रमशः साफ्टवेयर और हार्डवेयर) के क्षेत्र में वे अपने-अपने अनुभवों और वास्तविक सक्षमताओं का आदान-प्रदान करें।

संदर्भ :

1. विश्व व्यापार संगठन *इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स*, 2002
2. अग्रवाल, प्रदीप और प्रवाकर साहू (2003) : “चाइनाज अक्सेशन टु डब्ल्यूटीओ: इम्प्लीकेशंस फार चाइना एंड इंडिया,” *इकॉनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली*, 21-27 जून।

6.14 वर्ष 2002-03 के दौरान तेल और तेल से इतर घटकों के आयात में अत्यधिक वृद्धि के साथ आयात काफी तेजी से बढ़े हैं (परिशिष्ट सारणी VI.3)। जहां तेल से इतर वस्तुओं के आयात से घरेलू औद्योगिक गतिविधि तेजी के रूप में दिखाई दी है वहीं तेल के आयात में तीव्र वृद्धि इन कारणों से हुई - अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें वर्ष 2001-02 के दौरान 23 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर वर्ष 2002-03 के दौरान 27 डॉलर प्रति बैरल हो जाना, रिफाइनरी क्षमता में वृद्धि और कच्चे तेल का स्थिर घरेलू उत्पादन।

6.15 अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि और ग्रामीण मांग में कमी की वजह से सोने और चांदी के आयात में प्रत्यक्ष गिरावट आई है। सोने और चांदी के आयात को घटा दें तो भी तेल से इतर वस्तुओं के आयात में तीव्र वृद्धि हुई है। पूंजीगत वस्तुएं और निर्यात संबंधित मर्दों जैसे मोती और कीमती पत्थर, कच्चे काजू, टेक्सटाइल यार्न एवं फैब्रिक इसे बढ़ाने के मुख्य स्रोत थे। औद्योगिक मांग बढ़ जाने से, पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात मुख्यतया परिवहन उपकरण, ‘कंप्यूटर साफ्टवेयर सहित इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं’ और ‘इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़कर मशीनरी’ तथा विभिन्न

औद्योगिक कच्चे माल जैसे लुगदी एवं रदी कागज, लोहा और इस्पात, कृत्रिम राल (रेजिन) और प्लास्टिक सामग्री, तथा चिकित्सकीय एवं फार्मास्युटिकल उत्पादों में काफी विस्तार हुआ है। खाद्य तेल के आयातों में तीव्र वृद्धि हुई है जो सूखे की स्थिति के कारण बढ़ते घरेलू आपूर्ति मांग अंतर को प्रदर्शित करती है (सारणी 6.3 और परिशिष्ट सारणी IV.4)

6.16 सभी प्रमुख क्षेत्रों और देश समूहों से आयात में वृद्धि हुई है और विकासशील देशों के समूहों ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के भीतर अमरीका, बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से आयात में तीव्र वृद्धि हुई है। विकासशील देशों में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, मलेशिया और कीनिया आयात के प्रमुख स्रोत रहे हैं।

6.17 वर्ष 2003-04 (अप्रैल-जून) की पहली तिमाही के दौरान निर्यातों ने पिछले वर्ष की तदनुसूची अवधि के दौरान 14.4 प्रतिशत की तुलना में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी है। अप्रैल-जून 2003 के दौरान आयात में अप्रैल-जून 2002 के 6.7 प्रतिशत की तुलना में

सारणी 6.3 : भारत का चुनिंदा पण्यों का आयात

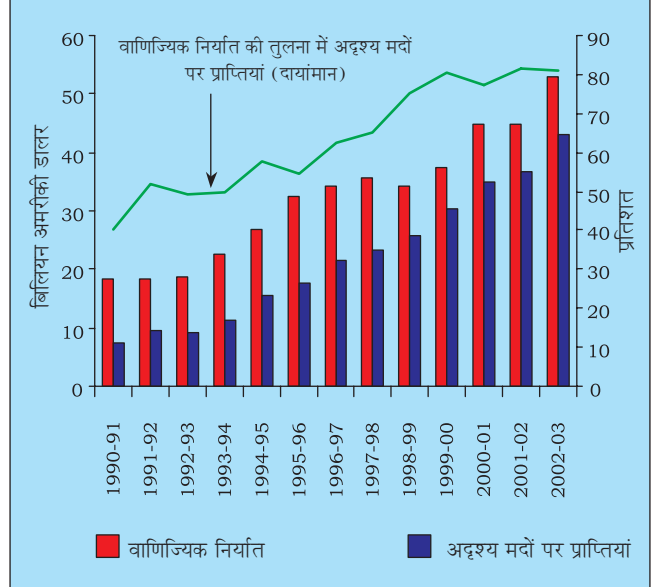
पण्य समूह	प्रतिशत अंतर	
	2002-03 अ	2001-02
1	2	3
पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और संबंधित सामग्री	26.0	-10.5
खाद्य तेल	33.3	3.6
उर्वरक	-13.5	-9.7
अलौह धातुएं	-0.4	21.2
कागज, पुट्टा और समाचार प्रिंट सहित विनिर्माण	-1.5	-0.9
कच्ची रबड़ सिंथेटिक और पुननिर्मित सहित	3.8	14.8
लुगदी और रद्दी कागज	15.5	4.6
धातुमय कच्ची धातु और धातु रद्दी	-12.3	47.7
लोहा और इस्पात	12.8	7.2
पूजीगत वस्तुएं	29.0	10.5
मोती, कीमती और अर्ध कीमती पत्थर	31.0	-3.8
टेक्सटाइल यार्न, फैब्रिक आदि	27.9	25.3
काजू, कच्चा काजू	181.3	-57.0
सोना और चांदी	-7.6	-1.2
कुल आयात	19.2	1.7
<i>ज्ञापन मदें</i>		
तेल से इतर आयात	16.7	7.2
सोना और चांदी को छोड़कर तेल से इतर आयात	20.0	8.5
अ: अनंतिम		
स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय		

27.0 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि हुई है। यह मुख्यतया तेल से इतर आयातों के कारण हुआ था जो पिछले वर्ष के 7.5 की तुलना में 30.9 प्रतिशत से बढ़ा। परिणामस्वरूप अप्रैल-जून 2003 के दौरान 1.8 बिलियन अमरीकी डालर से 4.2 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ गया।

अदृश्य मदें

6.18 1970 के दशक से भारत से अदृश्य मदों के निर्यात ने भुगतान संतुलन को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है, साथ ही इसने तेल की किल्लतवाले कठिन वर्षों में भी सहारा दिया है। वस्तुतः अदृश्य मदों के निर्यात बाजारों में सहसा नुकसान हो जाने से ही, अन्य बातों के साथ-साथ, 1990-01 के बाह्य भुगतान संकट की स्थिति बिगड़ती चली गई। तभी से, इसमें संघटनात्मक परिवर्तन करने से भारतीय विदेशी मुद्रा अर्जन में वृद्धि की स्थिति पैदा हो पाई है, जो सेवाओं की सक्रिय तुलनात्मक बेहतरी की ओर उन्मुखता दर्शाती है। वर्ष 2002-03 में अदृश्य मदों के प्रबल निर्यात विस्तार में काफ़ी हिस्सा रहा, जो वाणिज्यिक निर्यात में बढ़कर 81 प्रतिशत हो गया अर्थात सकल चालू प्राप्तियों का 45 प्रतिशत। प्रतिस्पर्धात्मकता में विशिष्ट सुधार को 1990-91 की स्थिति से तुलना करके मापा जा सकता है, जब अदृश्य

चार्ट VI.3 : भारत का वाणिज्यिक और अदृश्य मदों का निर्यात



मदों का निर्यात वाणिज्यिक निर्यात का 40 प्रतिशत था और चालू प्राप्तियों के एक तिहाई से भी कम था। (चार्ट VI.3)। विश्वव्यापी रूप से, अदृश्य मदों का चालू प्राप्तियों में हिस्सा मोटे तौर पर लगभग 35 प्रतिशत पर स्थिर रहा, जो भारत की अदृश्य मदों के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक तेजी के प्रति ध्यान केंद्रित करना दर्शाता है।

6.19 भारत की अदृश्य मदों की प्राप्तियों में अधिकांश हिस्सा निजी अंतरणों (मुख्यतया कामगारों द्वारा धन प्रेषण) का रहा है, इसके बाद व्यावसायिक सेवाएं और साफ्टवेयर का स्थान आता है (सारणी 6.4)। विदेशों में रोजगार कर रहे भारतीयों से प्राप्त विप्रेषण पारंपरिक रूप से अदृश्य मदों से आय का मुख्य स्रोत रहा है। विकासशील विश्व में निजी अंतरणों की प्राप्ति सबसे अधिक भारत में होती है जो वर्ष 2002-03 में 14.8 बिलियन अमरीकी

सारणी 6.4 : अदृश्य मदों से सकल प्राप्तियों की संरचना

1	प्रतिशत	
	2002-03	2001-02
2	3	
अंतरण	35.4	34.3
साफ्टवेयर सेवाएं	22.3	20.6
गैर-साफ्टवेयर विविध	21.2	20.4
यात्रा	7.0	7.9
परिवहन	5.9	5.4
आय	6.6	9.4
बीमा और जीएनआई	1.6	2.0
<i>ज्ञापन मदें</i>		
कुल प्राप्तियां (बिलियन अमरीकी डालर)	43.0	36.7
टिप्पणी : जीएनआई: अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी अंतरण		

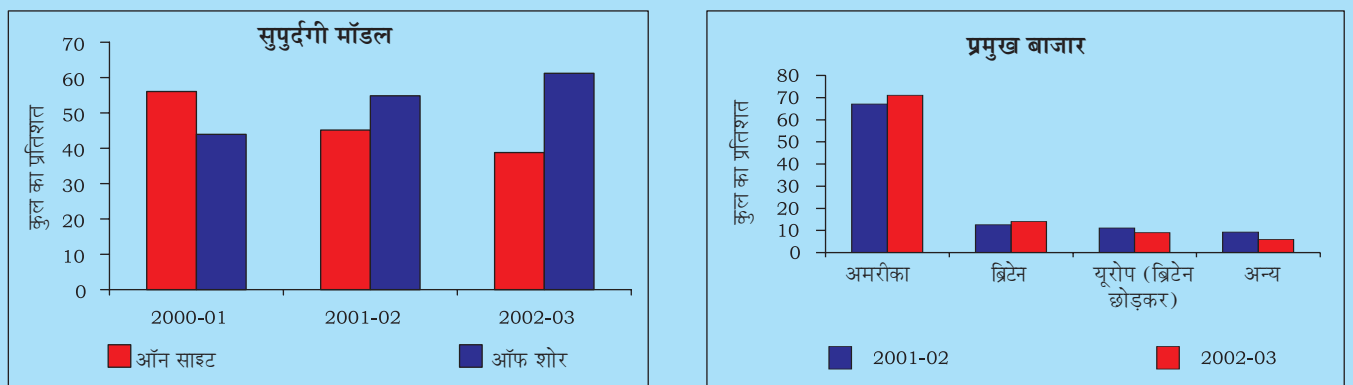
डालर था। विश्व के कुल अंतरणों में भारत का हिस्सा लगभग 3 प्रतिशत रहा है। विश्व अर्थव्यवस्था के विकासक्रम के अनुरूप कामगारों के विप्रेषण स्वरूप में दीर्घकालीन परिवर्तन हुए हैं। अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में करारबद्ध श्रमिकों से होनेवाली प्राप्तियों ने 1970 और 1980 के दशकों में खाड़ी देशों में आई तेजी ने मध्य पूर्वी देशों से व्यापक श्रमिक निर्यात आय के लिए रास्ता खोल दिया। 1980 के दशक के अंत तक भारत सहित कई बड़े श्रमिक निर्यातक देशों को वापसी प्रवसन की वजह से इसमें गिरावट का सामना करना पड़ा, क्योंकि खाड़ी केंद्रित श्रमिक निर्यात की तेजी मंद पड़ गई और इसका रुख बांगला देश तथा फिलीपीन की ओर हो गया। 1990 के दशक से भारत से मध्य पूर्वी देशों को निर्यात किए जानेवाले श्रमिक निर्यात का स्वरूप बदल गया है, भारतीय कामगारों के लिए पश्चिमी यूरोप और अमरीका प्रमुख गंतव्य बन गए हैं। श्रमिक बहिर्गमन के स्वरूप में हुए परिवर्तनों ने काफी हद तक बाजार का विशाखीकरण किया है। सफेदपोश और तकनीकी रूप से विशिष्टीकृत रोजगार के लिए कम कौशल की श्रेणियां खाली की जा रही हैं। लगभग 30 प्रतिशत धनप्रेषण अनिवासी रूपए जमाराशियों में से स्थानीय आहरण के रूप में होते हैं, जिन्हें निजी अंतरण में शामिल किया जाता है।

6.20 वर्ष 2002-03 के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात लगभग 27 प्रतिशत बढ़कर 9.6 बिलियन डालर का हो गया, जो विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था में चल रही निरंतर ‘‘प्रौद्योगिकी की मंदी’’ की स्थिति और विश्व इक्विटी बाजार में नई अर्थव्यवस्था की स्थिति के कमजोर होने के संदर्भ में असाधारण वृद्धि है। साफ्टवेयर उद्योग विलयन और अधिग्रहण के माध्यम से आधारभूत पुनर्संरचना के दौर से गुजर रहा है और बड़ी साफ्टवेयर कंपनियां विश्वव्यापी सुपुर्दगी क्षमता का निर्माण करने के लिए अपनी भर्ती संबंधी रणनीतियों को नवोन्मेषी बना रही हैं। भारतीय साफ्टवेयर में आए उत्थान का श्रेय नई सेवा लाइनों जैसे पैकेज साफ्टवेयर कार्यान्वयन, सिस्टम इंटीग्रेशन और नेटवर्क प्रबंधन की ओर विशाखीकरण को जाता है। वर्ष 2002-03 में जहां बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (बीएफएसआइ) विनिर्माण और दूरसंचार ध्यान आकर्षण के मुख्य

क्षेत्र रहे, वहीं साफ्टवेयर उद्योग की सेवाएं भी फुटकर कारोबार, उपयोगी वस्तुओं, टेलीकॉम सेवा प्रदाता तथा स्वास्थ्य रक्षा तक फैल गईं। उद्योग मानकों की तुलना में लघु तथा मध्यम उद्यमियों (एसएमइ) का कार्यनिष्पादन काफी अच्छा रहा। साफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ा, यह उद्योग की औसत वृद्धि से दुगुनी गति से बढ़ा है और कुल साफ्टवेयर निर्यात में इसका एक चौथाई योगदान है। आउटसोर्सिंग विरोधी कानून और वीजा प्रतिबंधों जैसी रुकावटों के बावजूद भारत बीपीओ के लिए वरीयता प्राप्त गन्तव्य स्थान रहा। इन गतिविधियों ने भारत के साफ्टवेयर उद्योग की कारोबार रणनीति के रूप में ऑफ शोर सुपुर्दगी को और भी मजबूती प्रदान की है। भारत के साफ्टवेयर निर्यात का प्रमुख गंतव्य स्थान अमरीका रहा। (चार्ट VI.4)।

6.21 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों के हमले के बाद पूरे विश्व में यात्रा, परिवहन, बीमा और कारोबारी सेवाओं पर आधारित वाणिज्यिक सेवाएं मंदी की स्थिति से गुजर रही हैं। हवाई यात्रा, बीमा और पर्यटन उद्योग विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार वर्ष 2002 में विश्वव्यापी वाणिज्यिक सेवाएं 5 प्रतिशत बढ़ी हैं। वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत 21 वें स्थान पर है और विश्व व्यापार में इसका हिस्सा 1.3 प्रतिशत है। हाल की घटनाओं की व्यापक प्रतिकूल परिस्थितियों से भारत की यात्रा सेवा का निर्यात प्रभावित हुआ है। आतंकवाद के भय और भौगोलिक राजनीतिक असुरक्षा के कारण भारत में पर्यटकों का आना धीमा रहा। वाणिज्यिक निर्यात में तीव्र वृद्धि से परिवहन प्राप्तियों में फायदा हुआ है। अन्य कारोबारी सेवाओं में तेजी से विस्तार हुआ है, जो अदृश्य आय का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गईं हैं। विनिमय और भुगतान के वातावरण में उत्तरोत्तर उदारीकरण से हाल के वर्षों में आई ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति के अनुरूप वाणिज्यिक सेवाओं के भुगतान बढ़ गए हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान यात्रा भुगतान में हुई वृद्धि पर्यटन के लिए की गई यात्रा और कारोबारी यात्रा दोनों के फलस्वरूप हुई है।

चार्ट VI.4 : भारत का साफ्टवेयर निर्यात



6.22 निवेश आय, जो विदेशी आस्तियों और देयताओं का शोधन दर्शाती है, के अन्तर्गत प्राप्तियां 2002-03 में अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों में गिरावट के कारण न्यून रहीं, जिसने विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियों के नियोजन से होने वाली आय को प्रभावित किया है। दूसरी ओर, सामान्य बने रहे ब्याज भुगतान की तुलना में लाभ और लाभांशों (प्रतिधारित आय सहित) के कारण निवेश आय भुगतान काफी अधिक रहा।

चालू खाता

6.23 वणििक और अदृश्य लेनदेनों की परस्पर गतिविधियों से वर्ष 2002-03 में चालू खाता शेष की प्रवृत्ति में संरचनागत परिवर्तन हुआ है। अन्य विकासशील देशों की भांति भारत में भी वणििक व्यापार घाटा ही बाह्य वित्तपोषण आवश्यकताओं को बढ़ाता है। भारत के मामले में एक जो गुणात्मक अंतर है वह अदृश्य खाते के निवल अधिशेष से वित्तपोषण सुविधा प्रदान करना है, जिससे बाह्य देयताओं के प्रति निर्भरता में कमी होती है। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में अदृश्य मदों ने वणििक व्यापार अंतर के लगभग दो-तिहाई हिस्से का वित्तपोषण किया था। वर्ष 2002-03 में पिछले वर्ष के समान अदृश्य खाता ही मुख्य घटक के रूप में उभरा है और उसने व्यापार घाटे को पूरा करते हुए चालू खाता में अधिशेष की स्थिति पैदा कर दी है (चार्ट VI.5)।

6.24 लगातार दूसरे वर्ष 2002-03 में चालू खाता की अधिशेष स्थिति का बने रहना 1990-91 के संकट की परिस्थितियों से उभरी व्यापक प्रवृत्ति का नतीजा है - बाह्य क्षेत्र से संबंधित नीतियों के लिए मध्यवर्ती लक्ष्य के रूप में सामान्य चालू खाता घाटे की एक सचेत नीति का चयन। इस नीतिगत परिवर्तन से होनेवाले फायदे भुगतान संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रारक्षित निधियों की संभाव्यता और विशिष्ट सुदृढ़ता से स्पष्ट हैं। 1997-98 के वित्तीय संकट की वजह से पूरे

सारणी 6.5: चालू खाता शेष : प्रमुख अर्थव्यवस्थाएँ

(बिलियन अमरीकी डालर)

देश/क्षेत्र	2001-02	1999-2000	1995-96
1	2	3	4
जापान	100.6	117.4	87.7
पूर्वी एशिया (जापान को छोड़कर)	111.4	108.8	-24.1
यूरो क्षेत्र	21.3	-52.4	50.5
चीन	26.4	20.8	4.4
ताइवान, चीन	21.8	8.6	8.3
सिंगापुर	18.3	16.2	13.7
हॉंगकांग एसएआर	12.1	8.2	-4.1
कोरिया	7.2	18.4	-15.8
मलेशिया	7.3	10.5	-6.6
इंडोनेशिया	7.1	6.9	-7.0
थाइलैंड	6.9	10.9	-14.1
फिलीपीन	4.4	8.2	-3.0
भारत	2.5	-3.7	-5.8
संयुक्त राज्य अमरीका	-448.4	-351.6	-111.8

टिप्पणी : (-) घाटा दर्शाता है।

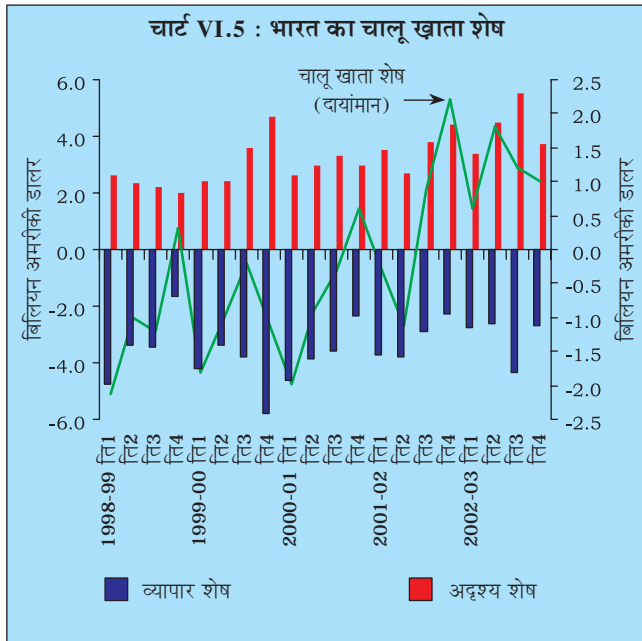
स्रोत : बीआइएस क्वाटरली रिव्यू, जून 2003

एशिया में उसी समय आई मंदी की जो प्रवृत्ति छा गयी उससे भारत प्रभावित नहीं रहा। इस आघात का समायोजन विभिन्न एशियाई देशों के स्थायी चालू खाता अधिशेष से परिलक्षित होता है क्योंकि मंदी की स्थिति ने आयात मांग को जकड़ रखा था (सारणी 6.5)। भारत में चालू खाता अधिशेष वर्ष 2002-03 के दौरान चालू प्राप्तियों में हुई 17.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ जुड़ा रहा। परिणामस्वरूप, ऋणचुकोती का अनुपात चीन और मलेशिया के बाद सबसे कम रहा और चालू प्राप्तियां/चालू भुगतान का अनुपात बढ़ती हुई आयात क्रय-शक्ति को दर्शाता है।

6.25 आंतरिक व्यापक स्थिति के साथ-साथ शेष राशियों की गतिविधियों की तुलना करते हुए भुगतान संतुलन के चालू खाता में अधिशेष की स्थिति बने रहने की जांच करना उपयुक्त होगा। सार्वजनिक क्षेत्र की बचत से अधिक व्यय की स्थिति इतनी खराब हो गयी कि उसे निजी क्षेत्र के बचत निवेश अधिशेष से भी संतुलित नहीं किया जा सका। यह स्पष्ट तथ्य बताता है कि यह निजी क्षेत्र का अधिशेष ही है, जो चालू खाता अधिशेष के रूप में झलकता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि व्यवसाय चक्र में उठान की शक्ति को मापने के लिए चालू खाता शेष के निहित घटकों की बारीकी से निगरानी की जाए।

पूंजी खाता

6.26 वर्ष 2002-03 में पूंजी खाता की गतिविधियां भुगतान संतुलन पर हावी रहीं और इस स्थिति में 1993-94 से प्रारंभ पूंजी आगम में आए उत्कर्ष से लेकर अब तक केवल एक बार 1995-96 में व्यवधान आया है। यह 1990-91 के संकट के दौरान बाहरी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत की रेटिंग कम कर देने की प्रक्रिया से भारतीय अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता के प्रति सतत अंतर्राष्ट्रीय विश्वास के अप्रभावित बने रहने को दर्शाता है। वर्ष 2002-03 में निवल पूंजी



का आगम इतना अधिक रहा जितना अब तक किसी एक वर्ष में नहीं रहा (परिशिष्ट सारणी VI.2)।

6.27 इस अवधि में पूंजी खाता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसमें कुछ परिवर्तन नीतिगत परिवर्तन के कारण हुए हैं, किंतु ये परिवर्तन उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की ओर हो रहे वित्तीय प्रवाहों के स्वरूप को भी उदघाटित करते हैं। अधिकारिक सहायता जो 1980 के दशक के अंत तक पूंजी खाते का मुख्य आधार रही, वर्ष 1995-96 से सामान्यतया निवल बहिर्गम (मूलधन चुकौती की निवल राशि और ब्याज भुगतान) को ही दर्शाती रही है। एशियाई विकास बैंक को 1.34 बिलियन अमरीकी डालर और विश्व बैंक को 1.68 बिलियन अमरीकी डालर के बहुपक्षीय ऋण की समय-पूर्वचुकौती के फलस्वरूप वर्ष 2002-03 में बहिर्गम में वृद्धि हुई है। कंपनियों द्वारा उच्च लागत वाले वाणिज्यिक ऋणों की समय-पूर्वचुकौती का भी प्रभाव इस पर पड़ा है। वर्ष 2002-03 में निवल बहिर्गम बढ़ गया, क्योंकि कंपनियों ने अपनी वित्तपोषण आवश्यकता के लिए घरेलू वित्तीय बाजार की ओर रुख कर लिया। औद्योगिक गतिविधियों में मंदी की स्थिति से 1998-99 से ही बाह्य वाणिज्यिक उधार को खपाने की प्रवृत्ति कमजोर बनी रही। इस प्रकार वर्ष 2002-03 में पूंजी खाता के दीर्घ एवं मध्यकालिक ऋण घटकों में संकुचन पैदा हुआ है जिसने बाह्य ऋण के समेकन चरण को विस्तार प्रदान कर दिया और इस तरह से 1990-91 की संकटकालीन स्थिति के समायोजन से लेकर अब तक बाह्य क्षेत्र प्रबंधन पर बाह्य ऋण का समेकन प्रमुख रहा है। पेट्रोल तेल और लुब्रिकेंट के आयात की उच्चतर मांग का वित्तपोषण करने के लिए अल्पकालीन ऋण प्रवाहों में वृद्धि हुई है (सारणी 6.6)।

6.28 अनिवासी जमाराशियों के अंतर्गत निवल आगम ऋण प्रवाह का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व है, जिसमें वर्ष 2002-03 में संरचनागत परिवर्तन हुए हैं। प्रत्यावर्तनीय रूप-मूल्यवर्ग के बाह्य रुपये खाते [एनआरइ(आर)ए] की जमाराशियों में तीव्र वृद्धि हुई, क्योंकि बंद कर दिए गए अप्रत्यावर्तनीय रूप खाते की जमाराशियों

सारणी 6.6 : पूंजी प्रवाह

(मिलियन अमरीकी डालर)

	2002-03	2001-02
1	2	3
विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	3,611	4,741
भारत में	4,660	6,131
विदेश में	-1,049	-1,390
संविभागीय निवेश	944	1,951
भारत में	979	2,020
विदेश में	-35	-69
बाह्य सहायता	-2,460	1,117
बाह्य वाणिज्यिक उधार	-1,698	-1,576
अल्पकालिक व्यापार ऋण	979	-891
अनिवासी (एनआरआइ) जमाराशियां	2,808*	2,754
बैंकिंग पूंजी (एनआरआइ जमाराशियों को छोड़कर)	5,435	2,838
अन्य पूंजी प्रवाह	3,019	-361
कुल पूंजी प्रवाह	12,638	10,573

* अर्नातिम

सारणी 6.7 : अनिवासी भारतीय जमा योजना के अंतर्गत जमाराशियां

(मिलियन अमरीकी डालर)

योजना	बकाया (मार्चांत)		निवल अंतर्वाह@	
	2003 अ	2002	2002-03 अ	2001-02
1	2	3	4	5
1. एफसीएनआर (बी)	10,193	9,673	520	594
2. एनआर(इ)आरए	14,716	8,449	5,987	1,626
3. एनआर(एनआर)				
आरडी	3,449	7,052	-3,704	508
कुल	28,358	25,174	2,803	2,728

@ सभी आंकड़ों में उपचित ब्याज शामिल है और मूल्यांकन परिवर्तन अमरीकी डालर की तुलना में डालर से इतर मुद्राओं में घट-बढ़ के कारण है।

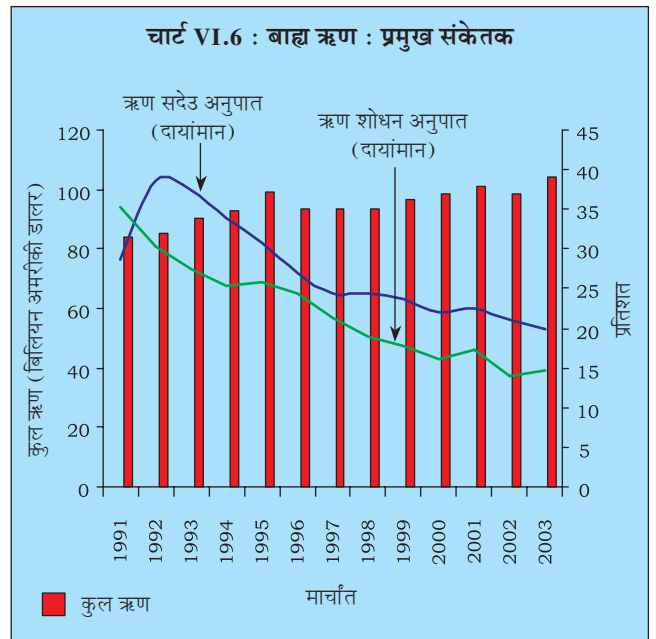
अ- अर्नातिम

टिप्पणी : वर्ष के दौरान विनिमय दर में हुई घटबढ़ के कारण हो सकता है कि रुपये जमाराशियों के बकाया स्टाकों में आये अंतर आपस में मेल न खाये।

[एनआर(एनआर) आरडी] की परिपक्वता राशियां, प्रत्यावर्तनीय योजना में डाल दी गईं। कुल मिलाकर, वर्ष के दौरान इन रूपए जमाराशियों के निवल आगम काफ़ी हद तक स्थिर बने रहे (सारणी 6.7)। विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की एफसीएनआर(बी) योजना के अंतर्गत निवल आगम कम बने रहने का कारण बेहतर विनिमय दर थी, जिसने रुपये जमाराशियों की स्पर्धा में उनके प्रतिलाभ को समायोजित किया है।

बाह्य ऋण

6.29 भारत का कुल बाह्य ऋण वर्ष में 5.5 बिलियन अमरीकी डालर बढ़ गया जो मार्च 2002 की समाप्ति पर 98.8 बिलियन अमरीकी डालर से मार्च 2003 की समाप्ति को 104.2 मिलियन डालर का हो गया (सारणी VI.6 और परिशिष्ट सारणी VI.10)। हालांकि वर्ष 2002-03 की अंतिम तिमाही के दौरान सरकार द्वारा एशियाई



विकास बैंक और विश्व बैंक को 3,030 मिलियन अमरीकी डालर के उच्च लागत वाले विदेशी ऋण की समय पूर्व चुकौती किए जाने के बावजूद भी यह वृद्धि हुई है। बाह्य ऋण में वृद्धि का मुख्य कारण अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) की जमाराशियां 6.8 बिलियन अमरीकी डालर तक और द्विपक्षीय ऋण का, मुख्य रूप से 1.5 बिलियन अमरीकी डालर की रियायत देने से बढ़ जाना, रहा है। कुल रियायती ऋण बढ़कर 3.1 बिलियन अमरीकी डालर हो गया है। एनआरआई जमाराशियों में हुई वृद्धि आंशिक रूप से तकनीकी स्वरूप की है, क्योंकि अब तक अप्रत्यावर्तनीय खाता अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमाराशियां खाता प्रत्यावर्तनीय खाता बना दिया गया है। अप्रत्यावर्तनीय रुपया जमाराशियों को बाह्य ऋण आंकड़ों से अलग रखा गया है। संघीय बजट 2002-03 में एनआरआई अप्रत्यावर्तनीय रुपया जमाराशि योजनाओं को बंद करने की घोषणा की गई है और इस खाते की राशियों को परिपक्वता पर खाताधारक के एनआरआई खाता (प्रत्यावर्तनीय) में अंतरित करने की अनुमति दी गई है। वर्ष 2002-03 के दौरान एनआरआई जमाराशियों में वास्तविक निवल वृद्धि 2.8 बिलियन अमरीकी डालर थी, जो पिछले वर्ष के दौरान हुई वृद्धि के समान ही रही है।

6.30 द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण का कुल ऋण स्टॉक में हिस्सा लगभग 45 प्रतिशत है (परिशिष्ट सारणी VI.10)। भारत सरकार ने निर्णय किया है कि जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, अमरीका, यूरोपियन देश और सोवियत संघ रूस को छोड़कर द्विपक्षीय साझेदारों से सहायता लेना बंद कर दिया जाए और जापान, जर्मनी, अमरीका तथा फ्रांस को छोड़कर साझेदारों को 7,491 करोड़ रुपए (1.6 बिलियन अमरीकी डालर के द्विपक्षीय ऋण की समयपूर्व चुकौती की जाएगी)। इस घटक के साथ जुड़े रियायतीपन और दीर्घावधि परिपक्वता ने चुकौती लागत के रूप में ऋण के समग्र स्टॉक पर अनुकूल प्रभाव डाला है। बाह्य वाणिज्यिक उधार (21.3 प्रतिशत) और दीर्घावधि अनिवासी जमाराशियां (22.5 प्रतिशत) बाह्य ऋण के अन्य प्रमुख घटक हैं।

6.31 ऋण स्थिरता के प्रमुख कारकों से ज्ञात होता है कि चुकौती क्षमता में निरंतर समेकन और सुधार की स्थिति बनी रही है। वर्ष के दौरान बाह्य ऋण सदेउ अनुपात 20.0 प्रतिशत घटा और कुल ऋण के प्रति अल्पावधि ऋण का अंश मार्च, 2002 के अंत के 2.8 प्रतिशत से बढ़कर 3.9 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2002-03 में 14.7 प्रतिशत के स्तर पर ब्याज चुकौती अनुपात निरंतर कम बना रहा। वर्ष 2002-03 के दौरान ऋण चुकौती और देयता चुकौती अनुपात में मामूली- सी वृद्धि अंतिम तिमाही में सरकारी ऋण की समयपूर्व चुकौती के कारण हुई है (सारणी 6.8)।

विदेशी निवेश

6.32 1990 के दशक से पूंजी खाते में उतार-चढ़ाव की स्थिति की एक महत्वपूर्ण विशेषता विदेशी निवेश का बढ़ता हुआ प्राधान्य रहा है, जो ऋण के समेकन के एक भाग के रूप में पूंजी आगम में नीतिगत अधिमानता के क्रम को दर्शाता है। 1996-97 में विदेशी निवेश प्रवाह काफी ऊंचाई पर

सारणी 6.8 : बाह्य ऋण का चुकौती स्वरूप भुगतान

(मिलियन अमरीकी डालर)

	2002-03	2001-02	2000-01
1	2	3	4
1. बाह्य सहायता@	6,308	3,240	3,706
2. बाह्य वाणिज्यिक उधार*	5,988	5,997	7,665
3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष #	0	0	26
4. अनिवासी भारतीयों की जमाराशि (ब्याज भुगतान)	1,268	1,555	1,659
5. रुपया ऋण चुकौती	474	519	617
6. कुल ऋण चुकौती	14,038	11,311	13,673
7. कुल चालू प्राप्तियां**	95,627	81,220	79,342
8. ऋण चुकौती अनुपात (6/7) (प्रतिशत)	14.7	13.9	17.2
9. चालू प्राप्ति अनुपात पर ब्याज भुगतान (प्रतिशत)	4.1	5.4	6.6
10. चालू प्राप्ति अनुपात की तुलना में ऋण (प्रतिशत)	109.0	121.6	127.5
11. देयता चुकौती अनुपात (प्रतिशत)	15.7	14.9	18.4

@ गैर-सरकारी लेखा सहित
* मध्यावधि, दीर्घावधि और अल्पावधि ऋणों पर ब्याज सहित
सकल संचयी आबंटन पर प्रभार को छोड़कर
** आधिकारिक अंतरणों को छोड़कर

टिप्पणी : 1. इस सारणी में ऋण चुकौती भुगतान स्थिति दिखाने के लिए भुगतान संतुलन के अनुरूप लेखांकन की अर्जन विधि अपनाई गई है, अतः उनमें तथा नकदी आधार पर लिए गए आंकड़ों में अंतर हो सकता है।
2. देयता चुकौती अनुपात, कुल चालू प्राप्तिओं के अनुपात के रूप में ऋण चुकौती भुगतान और लाभों एवं लाभांशों के विप्रेषण को एकसाथ दर्शाता है।

पहुंच गया वहीं 2001-02 में ऋण /इक्विटी अनुपात न्यूनतम होकर 0.2 तक रह गया। वर्ष 2002-03 के दौरान कमजोर स्टॉक बाजार स्थिति ने विदेशी निवेश प्रवाहों, प्रत्यक्ष और संविभाग दोनों को कम कर दिया है। जीडीआर/ एडीआर के माध्यम से जुटाई गई राशियों को बनाए रखा गया है। भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) संकलन को अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहार के समरूप बनाने के लिए एफडीआर से संबंधित आंकड़ों की व्याप्ति को वर्ष 2000-01 से बढ़ा दिया गया है और इसमें कतिपय नई मर्दे अर्थात गैर-निगमित निकायों की इक्विटी पूंजी, पुनः निवेश की गई आय और संबंधित संस्थाओं के बीच अंतर-कंपनी ऋण लेनदेन को शामिल किया गया है। तदनुसार, भारत में 2001-02 में विदेशी निवेश 6.1 बिलियन अमरीकी डालर था और 2002-03 में यह 4.7 बिलियन अमरीकी डालर रहा। (सारणी 6.9)। वर्ष 2002-03 में विदेश निवेश में गिरावट मुख्यतया इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और सेवा क्षेत्र में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय (एसआइए)/ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के माध्यम से आगमों में हुई गिरावट के कारण थी।

6.33 1990 के दशक की प्रवृत्ति के अनुरूप ही वर्ष 2002-03 के दौरान मारिशस और अमरीका में पंजीकृत कंपनियां भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की प्रमुख स्रोत रही हैं। अधिकांश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 'सेवा क्षेत्र' 'कंप्यूटर्स (हार्डवेयर और साफ्टवेयर)' तथा 'इंजीनियरिंग उद्योग' में हुए हैं (सारणी 6.10)।

सारणी 6.9 : भारत में श्रेणीवार विदेशी निवेश से प्राप्तियां

(मिलियन अमरीकी डालर)

	2002-03(अ)	2001-02 (सं)	2000-01 (सं)
1	2	3	4
क. प्रत्यक्ष निवेश (I+II+III)	4,660	6,131	4,029
I. इक्विटी (क+ख+ग+घ+ङ)	2,700	4,095	2,400
क) सरकार (एसआइए/एफआइपीबी)	919	2,221	1,456
ख) भारतीय रिजर्व बैंक	739	767	454
ग) अनिवासी भारतीय	-	35	67
घ) शेयरों का अधिग्रहण*	916	881	362
ङ) अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	126	191	61
II. पुनः निवेश की गई आय	1,498	1,646	1,350
III. अन्य पूंजी \$	462	390	279
ख. संविभाग निवेश (क+ख+ग)	979	2,021	2,760
क) जीडीआर/एडीआर #	600	477	831
ख) एफआइआइ@	377	1,505	1,847
ग) अपतटीय निधियां और अन्य	2	39	82
ग. कुल (क+ख)	5,639	8,152	6,789

अ - अर्न्तित सं. - संशोधित
 * फेमा 1999 की धारा 5 के अंतर्गत अनिवासियों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों के अधिग्रहण से संबंधित।
 # भारतीय कंपनियों द्वारा ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) और अमरीकी डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर) के माध्यम से जुटाई गई राशि।
 @ विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा निवल निधि आगम।
 \$ एफडीआइ संस्थाओं के अंतर-कंपनी ऋण लेनदेन से संबंधित आंकड़े।
टिप्पणी : 1. अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम संव्यवहारों के समरूप बनाने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेशगत आगमों की व्याप्ति को 2000-01 से बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2000-01 से एफडीआइ आंकड़ों में इक्विटी पूंजी के अलावा 'पुनःनिवेश की गई आय' (एफडीआइ कंपनियों की प्रतिधारित आय) और अन्य प्रत्यक्ष पूंजी (संबंधित संस्थाओं के बीच अंतर कंपनी ऋण लेनदेन। वर्ष 2002-03 के पुनः निवेश की गई आय के आंकड़ों का आकलन पिछले दो वर्ष का औसत है। अतः वर्ष 2000-01 से एफडीआइ के आंकड़ों की तुलना एफडीआइ के पिछले वर्षों के आंकड़ों से नहीं की जा सकती है।
2. यहां विदेशी निवेश के संबंध में दिए गए आंकड़े देश में कुल प्राप्तियां दर्शाते हैं और ये आंकड़े अन्य सारणियों जिनमें विदेशी निवेश के आधार पर प्रत्यक्ष आयात, विदेश में भारतीय निवेश तथा विनिवेश शामिल हैं, में दिए गए आंकड़ों से मेल नहीं खा सकते। ये आंकड़े इस रिपोर्ट के खंड V में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयर बाजार में किए गए निवल निवेश से संबंधित आंकड़ों से भी भिन्न हैं।

6.34 वर्ष 2002-03 में पूंजी प्रवाह की स्थिति बैंकिंग पूंजी में बड़े पैमाने पर उतार-चढ़ाव के जरिए संचालित होती रही है, जिससे विनिमय दर-प्रत्याशाओं और ब्याज-भिन्नता को देखते हुए विदेश में धारित आस्तियों का प्रत्यावर्तन परिलक्षित होता है (परिशिष्ट सारणी VI.2 और चार्ट VI.4)। पूंजी खाते के उत्तरोत्तर उदारीकरण से बैंकों की सीमा पार आस्तियों और देयताओं को प्रणालीगत स्थिरता की दृष्टि से महत्त्व दिया गया है। इसमें (i) आस्तियों और देयताओं की तुलना में अनिवासी तथा (ii) भारत में कार्यरत निवासी बैंकों (देशी और विदेशी दोनों) की आस्तियों और देयताओं की तुलना में विदेशों में निवासी, शामिल हैं। बैंक की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं के प्रमुख घटक ऋण और जमाराशियां, ऋण प्रतिभूतियां, इक्विटी शेयर, सहभागिता और कार्यशील पूंजी हैं। इस प्रकार, बैंकिंग के विदेशी मुद्रा आगमों में ऐसे बहुत से तत्व शामिल हैं जो देश के बाह्य ऋण का हिस्सा नहीं होते हैं। परिपक्वताधीन आधार पर, भारत में स्थित बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय

सारणी 6.10 : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश : देश-वार और उद्योग-वार प्राप्तियां*

(मिलियन अमरीकी डालर)

स्रोत	2002-03(अ)	2001-02	2000-01
1	2	3	4
कुल	1,658	2,988	1,910
देशवार प्राप्तियां			
मारीशस	534	1,863	843
संयुक्त राष्ट्र अमरीका	268	364	320
ब्रिटेन	224	45	61
जर्मनी	103	74	113
नीदरलैंड	94	68	76
जापान	66	143	156
फ्रांस	53	88	93
सिंगापुर	39	54	22
स्विट्जरलैंड	35	6	8
दक्षिण कोरिया	15	3	24
अन्य	227	280	194
उद्योग-वार प्राप्तियां			
रसायन और संबद्ध उत्पाद	53	67	137
कंप्यूटर	297	368	306
इंजीनियरी	262	231	273
इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उपकरण	95	659	213
वित्त	54	22	40
खाद्य और दुग्ध उत्पाद	35	49	75
फार्मास्युटिकल्स	44	69	62
सेवाएं	509	1,128	226
अन्य	309	395	578
अ- अर्न्तित			
* इस सारणी में दिए गए आंकड़ों में रिजर्व बैंक के माध्यम से अनिवासी भारतीयों से प्रत्यक्ष निवेश प्रणाली के अंतर्गत एफडीआइ प्राप्तियों और फेमा, 1999 की धारा 5 के अंतर्गत शेयरों के अधिग्रहण से हुई प्राप्तियों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।			

आस्तियां वर्ष 2002 में काफी हद तक अपरिवर्तित रही हैं, क्योंकि निवासियों को विदेशी मुद्रा में दिए गए ऋण में हुई वृद्धि जून 2002 और उससे आगे नास्ट्रो जमाराशियों में हुई गिरावट से लगभग संतुलित हो गई, जिससे कि बैंकों की घरेलू आस्तियों के प्रति वरीयता परिलक्षित होती है। बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय देयताएं मुख्यतया अनिवासी जमाराशियों के कारण बढ़ गई हैं। एनआरइ जमाराशियों में तीव्र वृद्धि से परिलक्षित होता है कि बंद कर दी गई एनआर (एनआर) आरडी की परिपक्व होनेवाली राशियों को इसमें डाल दिया गया है (सारणी 6.11)। अंतर्राष्ट्रीय आस्तियां और देयताएं प्रमुख रूप से अमरीकी डालर प्रधान थीं। संयुक्त राष्ट्र अमरीका बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों का गढ़ और देयताओं का प्रमुख स्रोत रहा। लगभग दो-तिहाई देयताओं की परिपक्वता छह महीने तक की थी। अंतर्राष्ट्रीय बैंक इसके प्रमुख लेनदार हैं, साथ ही बैंक से इतर निजी क्षेत्र भी इसमें शामिल थे।

अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति

6.35 अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आइआइपी) देश की बाह्य वित्तीय आस्तियों और देयताओं के लेखा-जोखा का संक्षिप्त अभिलेख है और जिसकी व्याप्ति बाह्य ऋण सांख्यिकी से कहीं अधिक रिकार्ड है,

सारणी 6.11 : भारत में बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय देयताएं और आस्तियां

(मिलियन अमरीकी डालर)

1	के अंत में बकाया			
	दिसंबर 2002	सितंबर 2002	जून 2002	मार्च 2002
2	3	4	5	
कुल अंतर्राष्ट्रीय देयताएं	39,914	38,295	37,456	35,110
<i>जिसमें से :</i>				
एफसीएनआर (बी) जमाराशियां	8,952	8,488	8,319	8,122
एनआरइ रुपया जमाराशियां	10,035	8,635	7,336	6,810
विदेशी मुद्रा उधारियां	2,654	2,142	2,198	1,130
बाण्ड (आरआइबी और आइएमडी सहित)	9,306	9,253	9,158	8,931
एनआरएनआर जमाराशियां	3,820	4,533	5,478	5,570
एडीआर और जीडीआर	801	779	755	382
विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (इएफसी) खाता	1,115	1,078	1,062	997
कुल अंतर्राष्ट्रीय आस्तियां	21,630	21,800	21,440	19,630
<i>जिसमें से :</i>				
निवासियों को प्रदत्त विदेशी मुद्रा ऋण	7,170	4,720	4,190	4,008
बकाया निर्यात बिल	3,440	3,300	3,200	3,113
नॉस्ट्रो राशियां	8,510	11,170	11,740	11,402
टिप्पणी : सभी आंकड़ों में उपचित ब्याज शामिल हैं। सभी शाखाओं से आंकड़े पूरी तरह से न मिल पाने से यहां दिए गए आंकड़े, हो सकता है सभी शाखाओं से लिए गए आंकड़ों से पूरी तरह से मेल न खाएं।				

बाह्य ऋण सांख्यिकी केवल उन्हीं बाह्य देयताओं तक सीमित है जिनकी सेवा के प्रति संविदात्मक बाध्यता है (बॉक्स VI.7)। अप्रत्यावर्तनीय जमाराशियां सहित विदेशी निवेश और बैंकिंग पूंजी जिन्हें अंततः बाह्य देयता माना जाता है, को आइआइपी के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। रिजर्व बैंक में इनका विभाजन बैंकिंग क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और कंपनियों सहित निजी क्षेत्र के रूप में कर देने से विदेशी आस्तियों और देयताओं के क्षेत्रवार उतार-चढ़ाव का मूल्यांकन करने में मदद मिली है।

6.36 मार्च 2002 तक की जानकारी से ज्ञात होता है कि 1997-2002 की अवधि के दौरान भारत की निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति में विशेष सुधार हुआ है जो रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा आस्तियों के निर्माण के फलस्वरूप निवल विदेशी देयताओं के लगभग 13 बिलियन अमरीकी डालर कम हो जाने से हुआ है। सकल विदेशी देयताओं में ऋण का हिस्सा सबसे अधिक है, उसके बाद संविभाग निवेश एवं भारत में प्रत्यक्ष निवेश एवं करेंसी और जमाराशियों का हिस्सा है। अन्य देयताएं जैसे व्यापार ऋण (आपूर्तिकार के 180 दिवसीय ऋण को छोड़कर), नॉस्ट्रो खाते की नामे राशियां और वास्ट्रो खाते की जमा राशियां तुलनात्मक रूप से कम रहीं। विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां सकल अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों की प्रमुख घटक रहीं (सारणी 6.12)।

बॉक्स VI.7

अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति- संरचना और तरीका

देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति मापने का भारत का बहुत पहले 1948 से सुदीर्घ इतिहास रहा है। प्रारंभ में यह 'भारत की विदेशी देयताओं और आस्तियों' के बेंचमार्क सर्वेक्षण के रूप में किया जाता था, जो 1956 से 'भारत में विदेशी निवेश' स्थिति के वार्षिक मूल्यांकन का पूरक बन गया और जिसे भारत में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों में लगी हुई विदेशी कंपनियों की भारतीय शाखाओं तथा विदेश द्वारा नियंत्रित भारतीय संयुक्त स्टॉक कंपनियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया जाता रहा है। 1963-64 के प्रारंभ से आइआइपी निजी क्षेत्र के संबंध तिमाही सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की जाने लगी ताकि भुगतान संतुलन के संकलन की अवधि से इसका सामंजस्य किया जा सके। वर्ष 1987 से विदेशी निवेश सर्वेक्षण जिसमें कंपनी और बैंकिंग क्षेत्रों को शामिल नहीं किया जाता, विदेशी आस्तियों और देयताओं की पंचवर्षीय गणना, मार्च 1997 के अंत तक की गई अद्यतन गणना (प्रथम गणना वस्तुतः जून, 1948 में गई थी) के लिए न्यूनतम मानदण्ड (बेंचमार्क) बना दिया गया। 1997-98 के वित्तीय संकट के बाद आइआइपी, इसकी व्याप्ति और पूंजी प्रवाह की संरचना पर नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने की इसकी व्यवहार्यता के कारण यह आकर्षण का केन्द्र बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह निर्धारित किया है कि इन आंकड़ों को अल्प रूप में वार्षिक आधार पर, किन्तु अधिमान्यतः तिमाही अंतराल पर उसके विशेष डाटा प्रसारण मानक (एसडीडीएस) के अंतर्गत प्रसारित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष डाटा प्रसारण

मानक (एसडीडीएस) के अनुसार भारत मार्च 2002 को समाप्त अवधि हेतु देश की आइआइपी का संकलन सितंबर 2002 तक करने के लिए कटिबद्ध था। तदनुसार, मार्च 1997 से लेकर मार्च 2002 तक की भारत की वार्षिक आइआइपी रिजर्व बैंक वेबसाइट पर डाल दी गई है।

आइआइपी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रत्यक्ष निवेश, संविभाग निवेश, अन्य निवेश एवं प्रारक्षित आस्तियों जैसे बृहत शीर्ष के अंतर्गत संस्तुत वर्गीकरण के तहत बाह्य वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं की स्थिति प्रस्तुत करती है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (अगस्त 2001) की सिफारिशों पर आइआइपी के संकलन की प्रणाली को पुनर्गठित किया गया है ताकि जहां कहीं इस स्थिति से संबंधित आंकड़े उपलब्ध न हों, वहां इन प्रसारित आंकड़ों का भरपूर उपयोग किया जा सके और प्रसारण कैलेण्डर का पालन भी हो सके।

इसकी वर्तमान प्रस्तुति में निम्नलिखित कतिपय महत्वपूर्ण श्रेणियों को शामिल किया गया है:

- प्रत्यक्ष निवेशकों (डीआइ) द्वारा प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों (डीआइइ) को दिए गए ऋण - प्रत्यक्ष निवेश देयता के 'अन्य पूंजी' के अंतर्गत वर्गीकृत
- क्रेता की उधार-साख - 'ऋण-अन्य क्षेत्र' के अंतर्गत वर्गीकृत
- अनिवासी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निवेश 'संविभाग निवेश' और 'मुद्रा और जमाराशि-मौद्रिक प्राधिकारी' के अंतर्गत विश्लेषित।

सारणी 6.12 : भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति

(मिलियन अमरीकी डालर)

मद	मार्च 2002अ	मार्च 2001अ	मार्च 1997
1	2	3	4
क. आस्तियां			
1. विदेश में प्रत्यक्ष निवेश	3,763	2,616	617
2. संविभागीय निवेश	493	498	282
2.1 इक्विटी प्रतिभूतियां	185	270	172
2.2 ऋण प्रतिभूतियां	308	228	110
3. अन्य निवेश	15,279	17,316	11,156
3.1 व्यापार ऋण	728	922	973
3.2 ऋण	1,989	1,768	548
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	9,049	10,873	5,287
3.4 अन्य आतियां	3,512	3,752	4,348
4. आरक्षित आस्तियां	54,715	42,897	26,714
कुल विदेशी आस्तियां	74,250	63,327	38,769
ख. देयताएं			
1. भारत में प्रत्यक्ष निवेश	23,690	20,053	10,630
2. संविभाग निवेश	31,650	31,376	18,743
2.1 इक्विटी प्रतिभूतियां	18,723	17,493	13,631
2.2 ऋण प्रतिभूतियां	12,927	13,883	5,113
3. अन्य निवेश	85,476	86,986	89,388
3.1 व्यापार ऋण	3,819	4,877	5,698
3.2 ऋण	62,846	63,993	67,743
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	18,508	17,807	15,300
3.4 अन्य देयताएं	303	309	646
कुल विदेशी देयताएं	1,40,816	1,38,415	1,18,762
निवल विदेशी देयताएं (ख-क)	66,566	75,088	79,992
निवल विदेशी देयताएं (सदेउ का प्रतिशत)	14.1	16.7	21.0

अ: अर्नातिम

टिप्पणी : आंकड़े आंशिक रूप से संशोधित किए गए हैं जो एफ बी आइ के विस्तारित कवरेज आंकड़ों और केवल वर्ष 2001 व 2002 हेतु बाह्य ऋण के संबंध में जुटाई गई जानकारी पर आधारित हैं। ये आंकड़े पिछले वर्षों के एफबीआइ के विस्तारित आंकड़ों से संबंधित सूचना की उपलब्धता और अन्य स्रोतों से प्राप्त अद्यतन जानकारी के आधार पर परिवर्तित हो सकते हैं।

विदेशी मुद्रा भण्डार

6.37 वर्ष 1993-94 (1995-96 को छोड़कर) से भुगतान संतुलन की स्थिति समग्र रूप से अधिशेष बनी रही है। विदेशी मुद्रा भण्डार के बढ़ते

संचय से यह स्थिति परिलक्षित होती है। वर्ष 2002-03 के दौरान हुआ संचय, किसी भी एक वर्ष का सबसे अधिक संचय था, जो स्वर्ण धारिता के अंतर्गत दर्ज मामूली मूल्यन प्राप्त सहित लगभग पूरी तरह से विदेशी मुद्रा आस्ति के रूप में था (सारणी 6.13)। विदेशी मुद्रा आस्तियों के संचय के प्रमुख स्रोत चालू खाता अधिशेष एवं विदेशी निवेश के रूप में प्राप्तियां, बैंकिंग पूंजी और अनिवासी जमाराशियां थीं। विनिमय दरों में विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव के फलस्वरूप मूल्य की दृष्टि से 3.8 बिलियन अमरीकी डालर की प्राप्ति हुई।

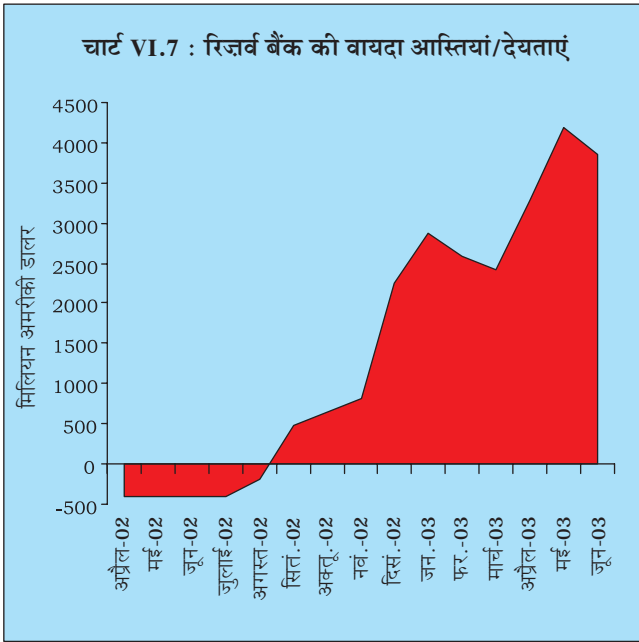
6.38 वर्ष 2002 के दौरान रिजर्व बैंक के वायदा बाजार परिचालनों से वर्तमान बकाया वायदा देयताएं समाप्त हो गई हैं और फलस्वरूप वायदा आस्तियों का सृजन हुआ है (चार्ट VI.7)।

6.39 15 अगस्त, 2003 को भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रारक्षित आस्तियों का भण्डार 85.4 बिलियन अमरीकी डालर था, जो उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं में छठा सबसे बड़ा भण्डार है। केवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में ही, जो विदेशी मुद्रा भण्डार का प्रमुख घटक है, (अन्य मानक घटक स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) हैं) मार्च 2003 के अंत के स्तर से ऊपर 10.0 बिलियन अमरीकी डालर के संचय के साथ भारत विश्व में सातवें स्थान पर है। विदेशी मुद्रा भण्डार की बढ़ती हुई शक्ति की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) की इस बात से परिलक्षित होती है कि उन्होंने अपनी वित्तीय लेनदेन योजना (एफटीपी) में भारत का उल्लेख ऋणदाता देश के रूप में किया है। भारत ने मार्च-मई 2003 में बुरुण्डी और जून 2003 में ब्राजील को आइएमएफ की वित्तीय लेनदेन (सहायता) योजना में भाग लिया है। विदेशी मुद्रा भण्डार की मात्रा और प्रबंध की गुणवत्ता का निर्धारण करने वाले प्रमुख मापदण्डों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए चुनिंदा देशों के समूह में वर्ष 2001 से भारत आइएमएफ के विशेष आंकड़ा प्रसारण मानक (एसडीडीएस) के अंतर्गत डाटा टेम्पलेट का ग्राहक बन गया है।

सारणी 6.13 : विदेशी मुद्रा भण्डार

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	स्वर्ण	विशेष आहरण अधिकार	विदेशी मुद्रा आस्तियां	कुल	निधि में भण्डार की स्थिति	आइएमएफ ऋण का बकाया उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
मार्च 1993	3,380	18	6,434	9,832	296	4,799
मार्च 1994	4,078	108	15,068	19,254	299	5,040
मार्च 1995	4,370	7	20,809	25,186	331	4,300
मार्च 1996	4,561	82	17,044	21,687	310	2,374
मार्च 1997	4,054	2	22,367	26,423	291	1,313
मार्च 1998	3,391	1	25,975	29,367	283	664
मार्च 1999	2,960	8	29,522	32,490	663	287
मार्च 2000	2,974	4	35,058	38,036	658	26
मार्च 2001	2,725	2	39,554	42,281	616	0
मार्च 2002	3,047	10	51,049	54,106	610	0
मार्च 2003	3,534	4	71,890	75,428	672	0
जून 2003	3,698	1	78,546	82,245	976	0



विदेशी मुद्रा भण्डार का प्रबंध-परिचालन

6.40 रिज़र्व बैंक को देश के विदेशी मुद्रा भण्डार के अभिरक्षक के रूप में शक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 से प्राप्त होती है। अधिनियम की धारा 17 रिज़र्व बैंक को विदेशी मुद्रा, विदेशी सरकारों द्वारा जारी बुलियन और प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय, तथा जमाराशियों/निवेशों को विदेशी केंद्रीय बैंक, विदेश में निगमित बैंक अथवा बहुपक्षीय बैंकिंग संस्थाओं में रखने के लिए प्राधिकृत करती है। ये उपबंध बाह्य आस्तियों के निवेश की संभावनाओं को भी परिभाषित करते हैं। प्रति-पक्ष/प्रतिभूतियों की साख गुणवत्ता पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। मोटे तौर पर, पात्र निवेश श्रेणियों में अन्य केंद्रीय बैंकों तथा अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) की जमाराशियां, विदेशी वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियां, ऋण लिखतें जो सरकारी/सरकार द्वारा गारंटीकृत देयता के रूप में हो और रिज़र्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य लिखत/संस्थाएं, शामिल हैं।

6.41 मुद्रा विन्यास और निवेश नीति सहित विदेशी मुद्रा भण्डार के प्रबंधन के लिए व्यापक रणनीति समय-समय पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से परामर्श करके तय की जाती है। विदेशी मुद्रा भण्डार के प्रबंधन में विदेशी मुद्रा भण्डार के दीर्घावधि मूल्य को बनाए रखना और सुरक्षा एवं चलनिधि के मूलभूत उद्देश्य के अनुरूप प्रतिलाभ के जोखिम तथा अस्थिरता को न्यूनतम करना, शामिल है। मुद्रा के विन्यास, अवधि और लिखतों को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा भण्डार की प्रबंध रणनीतियों की निरंतर समीक्षा की जाती है। एक आवधिक प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआइएस) रिपोर्ट विदेशी मुद्रा भण्डार के विन्यास में होने वाले परिवर्तनों के बारे में रिज़र्व बैंक प्रबंधन को अवगत कराते

रहना सुनिश्चित करती है।

6.42 विदेशी मुद्रा भण्डार में उतार-चढ़ाव मुख्यतया वायदा बाजार में किए गए छोटे-मोटे लेनदेन सहित, बाजार में रिज़र्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री करने से होता है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के संविभाग में धारित विदेशी मुद्रा आस्तियों के नियोजन से होनेवाली आय से उतार-चढ़ाव होता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के अनुरूप रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा भण्डार को अमरीकी डालर में दर्शाने की प्रथा अपनाता रहा है जिसका तात्पर्य यह है कि अमरीकी डालर में होनेवाला उतार-चढ़ाव विदेशी मुद्रा भण्डार के विन्यास में अपने हिस्से को प्रभावित करेगा। उल्लेखनीय है कि प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के अनुसार, भारत सहित अधिकांश देश विदेशी मुद्रा भण्डारे सही-सही मुद्रागत संरचना को आमतौर से प्रकाशित नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए कि केंद्रीय बैंकों में विभिन्न करेंसी में रखी आरक्षित निधियों में होने वाली अल्पावधि घट-बढ़ बाजार को संवेदनशील बनाती है।

6.43 निवेश पैटर्न से संबंधित निर्णय संविभाग प्रबंधन के व्यापक पैरामीटर के आधार पर लिए जाते हैं जिसमें पूंजी परिरक्षण और चल-निधि के प्रति विशेष आग्रह होता है। सभी प्रकार की विदेशी मुद्रा आस्तियों का निवेश ऐसी उच्चतम गुणवत्ता वाली आस्तियों में किया जाता है जिनमें अधिकांश भाग अल्प सूचना पर नकदी में परिवर्तनीय हो। संविभाग की सुनिश्चित बाध्यताएं होती हैं जैसे विभिन्न प्रतिभूतियों, करेंसियों, प्रतिपक्षों और सरकारों के संबंध में सीमाएं। जिन प्रतिपक्षों के साथ सौदा किया जा रहा है उनके आकार, पूंजी, रेटिंग, वित्तीय स्थिति और परिचालन क्षमता जैसे कारकों के अलावा उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और पिछले कार्यनिष्पादन रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में कड़ी चयन प्रक्रिया अपनायी जाती है। ये प्रतिपक्ष बैंक, बैंकों के सहयोगी अथवा प्रतिभूति गृह हो सकते हैं। जहाँ प्रतिभूतियों में निवेश सरकारी एवं सरकार द्वारा प्रत्याभूत लिखतों तक सीमित है, वहीं वर्तमान में इन लिखतों की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होती है। विदेशी मुद्रा भण्डार को श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों में रखने के साथ-साथ मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश किया जाता है।

6.44 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नीतिपरक उद्देश्यों के अनुसार विदेशी मुद्रा भण्डार के प्रबंध का परिचालन प्रारक्षित निधि संविभाग को दो भागों अर्थात् चलनिधि भाग और निवेश भाग में विभाजित करके किया जाता है। रिज़र्व बैंक के पास स्वतंत्र जोखिम मापदण्डों सहित दो बड़े संविभाग हैं अर्थात् मुद्रा बाजार संविभाग और बाण्ड संविभाग। मुद्रा बाजार संविभाग में एक वर्ष से कम की परिपक्वता वाले लिखत आते हैं और इनका संचालन मुख्यतया लेनदेन और हस्तक्षेप की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। मुद्रा बाजार संविभाग की अवधि छोटी होती है और ब्याज दर में उतार-चढ़ाव

को देखते हुए इसमें बाजार जोखिम कम होता है। इसके विपरीत, बाण्ड संविभाग में सरकारों और अधिराष्ट्रों द्वारा जारी तिहरे-ए/रेटिंग वाली लिखतों की दीर्घावधि धारिताएं होती हैं।

स्वर्ण भण्डार का प्रबंधन

6.45 भारतीय रिजर्व बैंक के पास 357 टन सोने की संतुलित धारिता है, जिसमें से 65 टन (कुल स्वर्ण धारिता का 18.2 प्रतिशत) विदेश में रखा हुआ है। स्वर्ण की धारिता वस्तुतः अपरिवर्तित रही है और स्वर्ण भण्डार का प्रबंधन यथार्थ रूप से किया जा रहा है। 1990-91 के भुगतान संतुलन संकट से बचाव के लिए स्वर्ण की संपार्श्विक जमानत पर बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड से ऋण लिए गए थे। नवम्बर 1991 में ऋण की चुकौती कर दिए जाने के बाद स्वर्ण को जमा के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैंड और अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक में रख दिया गया, ये जमा विशिष्ट अनुरोध पर किया गया क्योंकि वे आमतौर से स्वर्ण जमा स्वीकार नहीं करते। स्वर्ण जमा पर मामूली-सी आय का अर्जन होता है।

6.46 प्रारक्षित निधि आस्ति के रूप में स्वर्ण के महत्व को लेकर हाल के वर्षों में काफी नुकताचीनी हुई है। अन्य अधिकांश वित्तीय आस्तियों की तुलना में स्वर्ण कम अर्जन की आस्ति बना रहा है। फिर भी, संविभाग के विशाखीकरण का यह एक संभावनी मार्ग है। 1990-91 के संकट ने स्वर्ण के महत्व को 'अंतिम उपाय' की आस्ति के रूप में प्रमाणित कर दिया है और इसलिए स्वर्ण भण्डार के प्रबंधन हेतु सक्रिय प्रयास अपेक्षित हैं।

जोखिम प्रबंधन

6.47 विदेशी मुद्रा भण्डार के नियोजन के प्रति समग्र दृष्टिकोण यह है कि इसपर अधिक जोखिम से बचा जाए और इसपर सामान्य प्रतिलाभ प्राप्त किया जाता रहे। विदेशी मुद्रा भण्डार के प्रबंधन में आने वाले विभिन्न प्रकार के जोखिमों की पहचान करने, उन्हें मापने, उनकी निगरानी और नियंत्रण करने के लिए एक चुस्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की गई है।

- भारी चूक होने अथवा दायित्वों के भुगतान में विलंब से होने वाले ऋण जोखिम को केवल सरकारों एवं बैंकों और अधिराष्ट्रों द्वारा जारी कम से कम एएए रेटिंग वाले वित्तीय लिखतों में निवेश करके पूरा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक में जमाराशियां रखना भी जोखिम-मुक्त जमा माना जाता है। वाणिज्यिक बैंकों की जमाराशियों तथा वाणिज्यिक बैंकों/प्रतिभूति फर्मों के साथ विदेशी मुद्रा तथा बाण्डों/खजाना बिलों के लेनदेन हेतु अनुमोदित प्रतिपक्षों के चयन के लिए कड़े साख मानदण्ड हैं, प्रत्येक श्रेणी के लिए सीमाएं भी निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रतिपक्ष की श्रेणी और सीमा निर्धारित करने से पहले अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा विभिन्न अन्य वित्तीय मापदण्डों पर विचार किया जाता है। प्रतिपक्षों की दैनिक गतिविधियों पर नजर रखी जाती है ताकि भारी आशंकाओं के बीच उनकी साख गुणवत्ता का पता लगाया

जा सके। तदनुसार, ऋण सीमाओं में कटौती कर दी जाती है अथवा यदि आवश्यक हुआ तो इन प्रतिपक्षों को पूरी तरह से सूची से हटा दिया जाता है।

- विदेशी मुद्रा भण्डार का बहु-मुद्रा बहु-बाजार संविभाग में निवेश किया जाता है। विभिन्न मुद्राओं में किए जाने वाले निवेश (एक्सपोजर) के बारे में निर्णय उस मुद्रा में होने वाले उतार-चढ़ाव तथा अन्य दरम्यानी बातों जैसे मुद्रा भण्डार का अधिकांश भाग हस्तक्षेप करने वाली मुद्रा में बनाए रखना, बाह्य व्यापार इनवाइस प्रोफाइल के समतुल्य करेंसी प्रोफाइल सट्टा बनाए रखना और मुद्रा जोखिम के विशाखीकरण से होने वाले फायदे को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
- विदेशी मुद्रा संविभाग की ब्याजदर संवेदनशीलता, बेंचमार्क अवधि और बेंचमार्क के इर्द-गिर्द अनुमत विचलन से आंकी जाती है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि इसकी अवधि छोटी रखी जाए जिससे जोखिम न हो और चलनिधि बनी रहे। बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बेंचमार्क अवधि और विचलन की छूट में यथोचित रूप से परिवर्तन किया जाता है। निष्पादन मूल्यांकन के लिए प्रत्येक संविभाग हेतु एक बेंचमार्क निर्धारित है। यह बेंचमार्क रिजर्व बैंक प्रबंध-तंत्र द्वारा स्वीकृत और नियत जोखिम वहन क्षमता के आधार पर तैयार किया जाता है।
- लिखतों का चयन संविभाग की चलनिधि निर्धारित करती है। जहाँ एएए रेटिंग वाले सरकारी बाण्ड/खजाना बिल अत्यधिक अर्थसुलभ हैं, वहीं चलनिधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक की फिक्सबिस/डिस्काउंट फिक्सबिस रेटिंग वाले बाण्डों/बिलों को कभी भी नकदी में बदला जा सकता है। विदेशी मुद्रा भण्डार के विभिन्न घटकों के चलनिधि जोखिम की जांच का काम किया जा रहा है।
- आंतरिक रूप से, फ्रंट ऑफिस और बैंक ऑफिस दोनों के कार्य पूरी तरह अलग-अलग हैं और एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली सौदा करने, सौदे की प्रोसेसिंग और निपटान के स्तर पर कई प्रकार की जांच सुनिश्चित करती है। मिडिल ऑफिस की जिम्मेदारी जोखिम मापने एवं निगरानी, निष्पादन निगरानी और संगामी लेखा-परीक्षा की है। सौदे की प्रोसेसिंग और निपटान प्रणाली एकल बिंदु आंकड़ा प्रविष्टि सिद्धांत पर आधारित आंतरिक नियंत्रक दिशानिर्देशों के अधीन है और भुगतान संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है। उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु व्यापारियों के लिए आचार संहिता बनाई गई है।
- अधिकांश प्रतिभूतियां केंद्रीय बैंकों मुख्यतया यूनाइटेड इस्टेट फेडरल रिजर्व, द बैंक ऑफ इंग्लैंड और द बैंक ऑफ जापान की अभिरक्षा में हैं। सभी प्राथमिक नकदी खाते विदेशी केंद्रीय बैंकों में हैं। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक में किए गए निवेश के लिए वह अभिरक्षात्मक और

निवेश सेवाएं दोनों प्रदान करता है। बाह्य आस्ति प्रबंधकों द्वारा नियंत्रित अन्य प्रतिभूतियों और आस्तियों के छोटे भाग को चुनिंदा विश्वस्तरीय अभिरक्षकों की अभिरक्षा में रखा जाता है। अभिरक्षात्मक व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और अभिरक्षकों से संबंधित गतिविधियों का निरंतर रिकार्ड रखा जाता है ताकि जोखिम को न्यूनतम रखा जा सके।

लेखा-परीक्षा और निगरानी

6.48 समस्त आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देशों के संबंध में अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए कार्य प्रक्रिया से स्वतंत्र एक संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली बनाई गई है। इसके अलावा, प्रमुख मुद्राओं के संबंध में नॉस्ट्रो खाते का समाधान दैनिक आधार पर किया जाता है। रिजर्व बैंक के निरीक्षण विभाग द्वारा वार्षिक निरीक्षण और बाहरी लेखा-परीक्षकों द्वारा सांविधिक लेखा-परीक्षा के अलावा, एक प्रबंध लेखा-परीक्षक होता है जो डीलिंग रूम के लेनदेन की लेखा-परीक्षा करता है। इस प्रकार की लेखा-परीक्षा का मुख्य उद्देश्य जोखिम प्रबंधन प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है।

बाह्य आस्ति प्रबंधक

6.49 विदेशी मुद्रा भंडार का कुछ हिस्सा बाहरी आस्ति प्रबंधकों को इस उद्देश्य से सौंपा जाता है कि उनके बाजार अनुसंधान तक पहुंच बनी रहे और उसका लाभ मिल सके। इससे आस्ति प्रबंधकों के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकी का फायदा उठाने और बैंक के अपने डीलरों को प्रशिक्षण/एक्सपोजर देने में मदद मिलती है। आस्ति प्रबंधकों का चयन विश्वस्तरीय प्रतिष्ठित आस्ति प्रबंधन कंपनियों में से सावधानीपूर्वक किया जाता है। उन्हें स्पष्ट निवेश संबंधी दिशानिर्देश और बेंचमार्क दिए जाते हैं और उनके कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन मिडिल ऑफिस में एक अलग इकाई द्वारा आवधिक अंतरालों पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाण्ड और करेंसी बाजार के बारे में बाह्य आस्ति प्रबंधकों के विचारों एवं दृष्टिकोणों का परीक्षण किया जाता है और उन्हें परिचालनगत कार्यों के इनपुट के तौर पर प्रयोग किया जाता है।

विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और रिजर्व बैंक का तुलन पत्र

6.50 विदेशी मुद्रा आस्तियों को निर्गम विभाग (विदेशी प्रतिभूतियां) तथा बैंकिंग विभाग (विदेश में रखी राशियां और निवेश) में आस्तियों के रूप में रखा जाता है। स्वर्ण को भी निर्गम विभाग (स्वर्ण मुद्राएं एवं बुलियन के अंतर्गत) और बैंकिंग विभाग में रखा जाता है। यद्यपि एसडीआर भारत के अधिकृत विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा होते हैं, किंतु इन्हें भारत सरकार द्वारा रखा जाता है इसलिए इसे रिजर्व बैंक के तुलन पत्र में नहीं दिखाया जाता है।

6.51 विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन की मुख्य लेखांकन प्रथाएं इस प्रकार हैं: (i) दण्डात्मक ब्याज और लाभांश जिनकी गणना प्राप्ति आधार पर की जाती है, को छोड़कर सभी प्रकार की प्राप्ति एवं उपचित, किंतु अप्राप्त ब्याज/ छूट आयों को राजस्व खाते में लिया जाता है; ii) विदेशी मुद्रा और प्रतिभूति लेनदेन पर प्राप्त लाभ/हानि को भी राजस्व खाते में लिया जाता है; iii) करेंसी और स्वर्ण के पुनर्मूल्यन से हुए अप्राप्त लाभ/हानि को करेंसी और स्वर्ण पुनर्मूल्यन खाता (सीजीआरए) में लिया जाता है; iv) बाण्डों के पुनर्मूल्यन पर अप्राप्त हानियों को राजस्व खाते में ब्याज आय से प्रत्यक्ष कटौती के रूप में लिया जाता है; और v) बकाया वायदा स्थिति का पुनर्मूल्यन किया जाता है तथा यदि कोई हानि हो तो, उसे लाभ और हानि खाता में लिखा जाता है।

6.52 विदेशी मुद्रा आस्तियों के अंश के रूप में धारित बाण्डों / प्रतिभूतियों के मामले में, पुनर्मूल्यन प्रतिमाह महीने के अंत में बाजार मूल्यों के आधार पर किया जाता है। “बाजार का न्यूनतम अथवा बही मूल्य” सिद्धांत अपनाया जाता है अर्थात् यदि बाजार मूल्य बही मूल्य से कम है तो धारिता को बाजार मूल्य के हिसाब से लिखा जाएगा और बाद में इसे परिवर्तित नहीं किया जाता है, भले ही बाजार मूल्य बढ़ जाए। विदेशी मुद्रा भंडार से होने वाली आय को रिजर्व बैंक की अन्य आय के साथ जोड़ दिया जाता है।

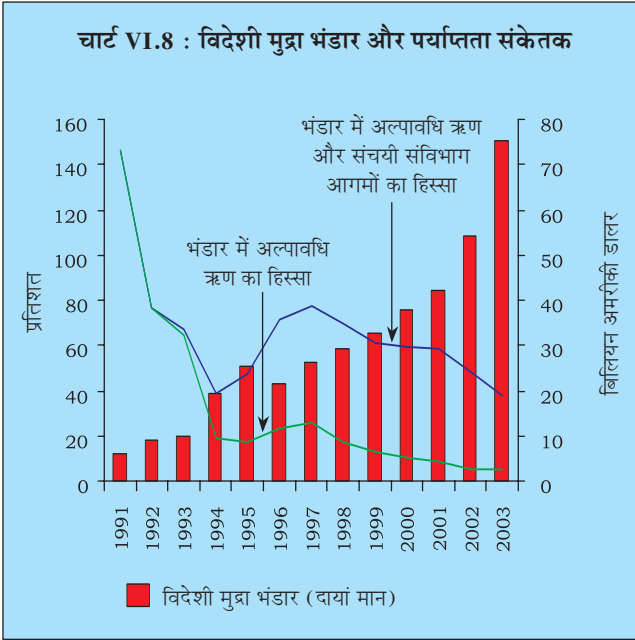
पारदर्शिता संबंधी मामले

6.53 अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी मुद्रा धारिताएं सार्वजनिक प्रकटीकरण के सर्वोत्तम मानकों के अधीन होती हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन से संबंधित नीति, अर्धवार्षिक मौद्रिक और ऋण नीति वक्तव्य के माध्यम से स्पष्ट कर दी जाती है। रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष भर की गतिविधियों का परिदृश्य प्रस्तुत करती है। विदेशी मुद्रा भंडार में होने वाली घट-बढ़ की सूचना रिजर्व बैंक की मासिक बुलेटिन के साप्ताहिक सांख्यिकीय संपूरक (डब्ल्यूएसएस) में दी जाती है। रिजर्व बैंक की बकाया वायदा स्थितियों सहित इसकी खरीद और बिक्री की स्थिति बुलेटिन में मासिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। विदेशी मुद्रा भंडार के नियोजन और वायदा स्थिति सहित बहुत से मापदण्डों के बारे में जानकारी आइएमएफ और रिजर्व बैंक की वेबसाइटों पर आइएमएफ-एसडीडीएस के अंतर्गत दी गई है।

विदेशी मुद्रा भंडार की धारिताओं की लागत

6.54 विदेशी मुद्रा भंडार का संचय, आयात आवश्यकताओं को पूरा करने, अप्रत्याशित आकस्मिकताओं और विभिन्न प्रकार की पूंजी प्राप्तियों से जुड़े “चलनिधि जोखिमों” से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त स्तर बनाए रखने की रिजर्व बैंक की नीति को उदघाटित करता है। इस स्तर तक भंडार रखना मौद्रिक और विनिमय दर नीतियों में विश्वास बने रहने के मूल उद्देश्य को पूरा करता है, हस्तक्षेप की क्षमता बढ़ाता है और अस्थिरता को कम करता है तथा बाजारों को विश्वास प्रदान करता है (चार्ट VI.8)।

चार्ट VI.8 : विदेशी मुद्रा भंडार और पर्याप्तता संकेतक



6.55 हाल की अवधि में विदेशी मुद्रा भंडार में हुई पर्याप्त वृद्धि ने विदेशी मुद्रा भंडार को बनाए रखने की लागतों एवं लाभों को लेकर बहस का मुद्दा बना दिया है। विकासशील देशों के लिए, अनिश्चितता की अवधि के दौरान विनिमय दर में तीव्र घट-बढ़ काफी असंतुलन पैदा कर सकती है और अर्थव्यवस्था के लिए महंगी साबित हो सकती है। वित्तीय संकट की लागतें सकल देशी उत्पाद और कल्याण की क्षति के रूप में हानिकर होती हैं। ये आर्थिक लागतें, विदेशी मुद्रा भंडार धारिता की निवल वित्तीय लागत से कहीं अधिक हो सकती हैं जो घरेलू आस्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार के नियोजन की अवसर लागत और विदेशी मुद्रा आस्तियों के वास्तविक नियोजन से अर्जित प्रतिफल के बीच के अंतर के रूप में विशिष्ट रूप से मापी जाती हैं। हाल की अवधि में विदेशी मुद्रा भंडार में हुई वृद्धि रिजर्व बैंक द्वारा घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार में की गई निवल खरीद से हुई है। इसी के बराबर घरेलू मुद्रा की राशि प्रतिपक्षों को बेच दी जाती है जिन्हें उस राशि को घरेलू आस्तियों में निवेश करने और रुपए-मूल्यवर्ग में प्रतिलाभ कमाने की स्वतंत्रता होती है। हाल की अवधि में विदेशी मुद्रा भंडार में हुआ संचय बाह्य ऋण के समग्र स्तर को बढ़ाए बिना ही हुआ है, बल्कि यह संचय श्रमिकों के अधिक धनप्रेषणों, निर्यात आगमों के तत्काल प्रत्यावर्तन और ऋण से इतर प्राप्तियों से हुआ है। यहां तक कि विदेशी मुद्रा मूल्य-वर्ग के अनिवासी जमाराशियों के प्रवाह (जहां ब्याज दरें लिबॉर से जुड़ी हैं) को यदि शामिल कर लिया जाए, तो भी भारत में अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भंडार के संचय की वित्तीय लागत काफी कम रही है, और लागत की कमी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भंडार पर मिलने वाले प्रतिफल से समायोजन के बाद और भी कम हो सकती है।

6.56 विदेशी मुद्रा भंडार की धारिता के संबंध में किसी भी लागत लाभ विश्लेषण में विदेशी मुद्रा भंडार की धारिता के उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ये बिंदु भी शामिल हैं : (क) मौद्रिक और विनिमय दर नीतियों में विश्वास कायम रखना (ख) विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करने की क्षमता बढ़ाना; (ग) बाह्य असुरक्षा को सीमित करना ताकि संकट के समय आघातों को वहन किया जा सके; (घ) बाजारों को यह विश्वास दिलाना कि बाह्य देयताएं हमेशा पूरी की जा सकती हैं; (ङ) बाह्य आस्तियों द्वारा घरेलू मुद्रा को समर्थन देते हुए बाजार सहभागियों की सुभीता को बढ़ाना; तथा (च) विदेशी मुद्रा बाजार की अस्थिरता को कम करना।

6.57 हाल की अवधि में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए समग्र रूप से अपनाया गया दृष्टिकोण विशिष्ट कारकों एवं अन्य आकस्मिकताओं को ध्यान में रखकर न्यायोचित तरीके से बनाया गया है। इन कारकों में अन्य बातों के साथ-साथ ये बातें भी शामिल हैं: चालू खाता घाटे की राशि की मात्रा; अल्पावधि देयताओं (दीर्घावधि ऋणों पर वर्तमान चुकौती बाध्यताओं सहित) का आकार; संविभाग निवेशों एवं अन्य प्रकार के पूंजी प्रवाहों में संभावित घट-बढ़; बाहरी आघातों और अनिवासी भारतीयों की प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा जमाराशियों में घट-बढ़ के फलस्वरूप भुगतान संतुलन पर पड़ने वाला अप्रत्याशित दबाव। विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त उच्च स्तर रखना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक लंबी अनिश्चितता की स्थिति पैदा होने पर भी विदेशी मुद्रा भंडार एक उपयुक्त लंबी अवधि तक सभी खातों “चलनिधि के जोखिम” को पूरा कर सके। इतना ही नहीं, दीर्घावधि में विदेशी मुद्रा भंडार की मात्रा अर्थव्यवस्था में वृद्धि और जोखिम-समायोजित पूंजी प्रवाह की मात्रा के अनुरूप होना चाहिए जो अचानक घटित हो सकने वाली प्रतिकूल अथवा अप्रत्याशित गतिविधियों के प्रति अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करती है।

6.58 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के “विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन संबंधी दिशानिर्देश” के संपूरक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित हाल ही के दस्तावेज में एक मामले पर अध्ययन के लिए चयनित 20 देशों में से भारत एक था। आइएमएफ ने पाया है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन सामान्य रूप से आइएमएफ के दिशानिर्देशों के अनुरूप है जिसकी तुलना इस क्षेत्र में विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं से की जा सकती है। हाल की अवधि में विश्वव्यापी गतिविधियों के अनुरूप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन-कार्य और अधिक पारदर्शी हो गया है। विदेशी मुद्रा भंडार के कुशल प्रबंधन पर जोर दिया जाता है। कुछ क्षेत्रों जैसे-सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर और अधिक कुशल प्रयोग, परिष्कृत जोखिम प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग जैसे जोखिम पर मूल्य (वीएआर), इष्टतम मुद्रा विन्यास का निर्धारण, ऋण और बाजार जोखिमों का सुदृढ़ प्रबंधन तथा आंतरिक नियंत्रण संरचना में भारत की नीतियों की तुलना अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से की जा सकती है।